राष्ट्रीय हिन्दी दैनिक

क्रांति समय

कार्यालय ऑफिस

क्रांति समय दैनिक समाचार में
प्रेसनोट, नोटिस, वेपार संबंधित संपर्क करें
पता:- एस.टी.पी.आई-सुरत-395023
संपर्क नं.-7490923915
ईमेल:-info.krantisamay@gmail.com

सुरत गुजरात से प्रकाशित, मुंबई, उत्तरप्रदेश, बिहार, राजस्थान, मध्यप्रदेश, उत्तरांचल, उत्तराखंड, दिल्ली, हरियाणा में प्रकाशित

सुरत-गुजरात, संस्करण सोमवार 29 दिसंबर 2025 वर्ष-8,अंक-302 पृष्ठ-08 मूल्य-01 रूपये

Website : www.krantisamay.com & epaper.krantisamay.com www.facebook.com/krantisamay1 www.twitter.com/krantisamay1

पहला कॉलम

मैं ट्रांसपोर्ट मंत्री हूं, मैंने डंडा कर कहा..... डीजल और पेट्रोल बंद करो वरना

मुंबई । नागपुर में केंद्रीय सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री नितिन गडकरी ने पेट्रोल और डीजल के विकल्पों को लेकर बड़ा बयान दिया है। केंद्रीय मंत्री गडकरी ने कहा कि वह ट्रांसपोर्ट मंत्री हैं और उन्होंने पेट्रोल-डीजल पर निर्भरता कम करने के लिए सख्त रुख बनाया है। उन्होंने कहा, मैं ट्रांसपोर्ट मंत्री हूं। मैंने डंडा लगाया है। डीजल और पेट्रोल बंद करो वरना यूरो 6 के इमिशन नॉर्म्स लगाऊंगा। केंद्रीय मंत्री गडकरी ने कहा कि अब ट्रैक्टर कंपनियों ने फ्लेक्स इंजन तकनीक पर काम शुरू कर दिया है। उन्होंने बताया कि 100 फीसदी इथेनॉल और सीएनजी से चलने वाले फ्लेक्स इंजन ट्रैक्टर अब तैयार हो चुके हैं। उन्होंने बताया कि केंद्र सरकार वैकल्पिक ईंधन को बढ़ावा देने के लिए आर्थिक मदद भी दे रही है। गडकरी के मुताबिक, आने वाले दिनों में कंस्ट्रक्शन इक्यूपमेंट के लिए जो लोग फाइनेंस कराते हैं, अगर वे अल्टरनेटिव फ्यूल और बायो फ्यूल वाले विकल्प चुनते हैं, तब उन्हें पांच फीसदी सब्सिडी मिलेगी। इसका मकसद इन तकनीकों को ज्यादा से ज्यादा प्रमोट करना है। केंद्रीय मंत्री ने बताया कि हाल ही में तीन ट्रक लांच किए गए हैं। इसमें से दो ट्रक हैं, जिसमें डीजल और पेट्रोल इंजन के साथ हाइड्रोजन मिलाकर इस्तेमाल किया है। जबकि एक ट्रक पूरी तरह हाइड्रोजन फ्यूल सेल पर चलता है। केंद्रीय मंत्री गडकरी ने कहा कि देश का भविष्य अल्टरनेटिव फ्यूल और बायो फ्यूल से जुड़ा हुआ है और आने वाले समय में यही रास्ता भारत को आगे ले जाएगा।

छात्रों के प्रस्तावित विरोध प्रदर्शन में शामिल होने वाले नेता नजरबंद..... महबूबा, इल्तिजा और रुहुल्लाह मेहदी

जम्मू। जम्मू कश्मीर में मौजूदा आरक्षण नीति के खिलाफ छात्रों के प्रस्तावित विरोध प्रदर्शन में शामिल होने से रोकने के लिए पीपुल्स डेमोक्रेटिक पार्टी (पीडीपी) अध्यक्ष और पूर्व सीएम महबूबा मुफ्ती और नेशनल कांफ्रेंस के सांसद आगा सैयद रुहुल्लाह मेहदी सहित कई नेताओं को नजरबंद किया गया। अधिकारियों ने बताया कि महबूबा मुफ्ती, उनकी बेटी इल्तिजा मुफ्ती, श्रीनगर से लोकसभा सदस्य रुहुल्लाह मेहदी, पीडीपी नेता वहीद पारा और श्रीनगर के पूर्व महापौर जुनैद मट्टू को उनके घरों में नजरबंद किया गया। जिला प्रशासन ने कदम इन नेताओं द्वारा उन छात्रों के साथ एकजुटता व्यक्त प्रकट करने के बाद उठाया, जिन्होंने गुपकर रोड पर शांतिपूर्ण विरोध प्रदर्शन करने की योजना बनाई थी। इन नेताओं ने मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला द्वारा मुद्दे के समाधान के लिए समिति गठित करने के एक साल पूरे होने के बावजूद कोई सकारात्मक नतीजा नहीं निकलने पर छात्रों की ओर से आयोजित मार्च में शामिल होने की बात कही थी। इस घटनाक्रम पर प्रतिक्रिया देकर नेता पारा ने कहा कि यह दुर्भाग्यपूर्ण है कि नेताओं को घर में नजरबंद कर दिया गया है ताकि वे विरोध कर रहे छात्रों के साथ एकजुटता न प्रकट कर सकें।

अरावली विवाद पर आज सुप्रीम कोर्ट में सीजेआई की अध्यक्षता वाली पीठ करेगी सुनवाई

नई दिल्ली। अरावली पहाड़ियों की परिको लेकर उठे विवाद के बीच सुप्रीम कोर्ट ने इस मुद्दे पर स्वतः संज्ञान लिया है और वह सोमवार को मामले की सुनवाई करेगा। सीजेआर सूर्यकांत की अध्यक्षता वाली अवकाशकालीन पीठ इस मामले की सुनवाई करेगी, जिसमें न्यायमूर्ति जे के माहेश्वरी और न्यायामूर्ति ऑगस्टीन जॉर्ज मसीह शामिल हैं। सुप्रीम कोर्ट ने 20 नवंबर को अरावली पहाड़ियों और पर्वतमालाओं की एक समान परिको स्वीकार करते हुए, दिल्ली, हरियाणा, राजस्थान और गुजरात में फैले अरावली क्षेत्रों में विशेषज्ञों की रिपोर्ट आने तक नए खनन पट्टों के आवंटन पर रोक लगा दी थी। कोर्ट ने पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय की एक समिति की सिफारिशों को स्वीकार किया था।

विकसित भारत के लिए स्वस्थ समाज जरूरी, चिकित्सकों की भूमिका अहम : अमित शाह

*** आईएमए शताब्दी समारोह में नव-निर्वाचित पदाधिकारियों का शपथ ग्रहण, हेल्थ इकोसिस्टम और मेडिकल एथिक्स पर दिया जोर**

अहमदाबाद ।

केंद्रीय गृह एवं सहकारिता मंत्री अमित शाह और मुख्यमंत्री भूपेंद्र पटेल की प्रेरक उपस्थिति में रविवार को इंडियन मेडिकल एसोसिएशन के नव-निर्वाचित पदाधिकारियों का शपथ ग्रहण समारोह अहमदाबाद में आयोजित किया गया। इस अवसर पर केंद्रीय गृह एवं सहकारिता मंत्री अमित शाह ने इंडियन मेडिकल एसोसिएशन की शताब्दी के उपलक्ष्य में सभी को शुभकामनाएं दीं और कहा कि देश में होलिस्टिक व्यू के साथ हेल्थ इकोसिस्टम का निर्माण हो रहा है। प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी के नेतृत्व में देश में स्वच्छता मिशन, फिट इंडिया मूवमेंट, खेलो इंडिया, योग दिवस का आयोजन, आयुष्मान भारत योजना, आभा और इंद्रधनुष अभियान, जेनेरिक दवाओं को प्रोत्साहन, साथ ही टेलीमेडिसिन और वीडियो कॉन्फ्रेंस के माध्यम से मार्गदर्शन जैसे प्रयास किए गए हैं। उन्होनें जोड़ा कि देश में हेल्थ इन्फ्रास्ट्रक्चर के विकास के लिए 1,65,000 करोड़ रुपए आवंटित किए गए हैं। देश का स्वास्थ्य बजट वर्ष 2013-14 में 37,000 करोड़ रुपए से बढ़ाकर आज 1,28,000 करोड़ रुपए किया गया है, जिससे स्वास्थ्य क्षेत्र में कई सकारात्मक परिवर्तन देखने को मिल रहे हैं।

केंद्रीय मंत्री ने आगे कहा कि विकसित भारत के संकल्प को साकार करने के लिए हेल्दी डेमोग्राफी आवश्यक है और इसमें चिकित्सकों की भूमिका अत्यंत महत्वपूर्ण है। उन्होंने कहा कि चिकित्सकों को बीमारी की बजाय वेलनेस पर ध्यान केंद्रित करना चाहिए। कोरोना काल में देशभर के चिकित्सकों द्वारा दी गई सेवाओं की हृदय से सराहना करते हुए केंद्रीय मंत्री ने आयुष्मान भारत योजना और जेनेरिक दवाओं के प्रति चिकित्सकों द्वारा सकारात्मक वातावरण तैयार करने की अपेक्षा व्यक्त की। उन्होंने कहा कि बदलते समय के साथ चिकित्सा क्षेत्र के एथिक्स के मानकों को भी पुनर्परिभाषित करने की आवश्यकता है। इंडियन मेडिकल एसोसिएशन जैसी संस्थाओं को मेडिकल एथिक्स को रिडिफाइन करने के प्रयास करने चाहिए। मेडिकल कॉलेजों में भावी डॉक्टरों को एथिक्स की समझ के साथ तैयार कर देश को अच्छे डॉक्टर मिलें, यह सुनिश्चित किया जाना चाहिए। केंद्रीय मंत्री ने कहा कि आईएमए द्वारा की जा रही सेवाकीय गतिविधियों की सराहना की और आईएमए से जुड़े चिकित्सकों से टेलीमेडिसिन तथा वीडियो काउंसलिंग जैसी गतिविधियों में सक्रिय भागीदारी की अपील की। उन्होंने आशा व्यक्त की कि एसोसिएशन चिकित्सकों की मांगों को प्रस्तुत करने के साथ-साथ देश के स्वास्थ्य क्षेत्र को और अधिक मजबूत बनाने में भी योगदान देगा। अमित शाह ने नव-निर्वाचित राष्ट्रीय अध्यक्ष डॉ. अनिल नायक को ऊर्जावान बताते हुए शुभकामनाएं व्यक्त कीं कि उनके नेतृत्व में एसोसिएशन को नई ऊर्जा और गति मिलेगी।

मन की बात में बोले पीएम मोदी-

भारत ने रचा विज्ञान, अंतरिक्ष, खेल और संस्कृति में सुनहरा इतिहास भारत की ऐतिहासिक उपलब्धियां

गुजरते साल ने गर्व का अवसर दिया और देश को आत्मविश्वास से भर दिया

नई दिल्ली।

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने रविवार को 'मन की बात' कार्यक्रम के 129वें संस्करण में वर्ष 2025 की प्रमुख उपलब्धियों और यादगार पलों को याद करते हुए देश को संबोधित किया। उन्होंने कहा कि 2025 ऐसा वर्ष रहा, जिसने हर भारतीय को गर्व करने का अवसर दिया और देश को आत्मविश्वास से भर दिया।

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा, कि विज्ञान और अंतरिक्ष के क्षेत्र में भारत ने बड़ी छलांग लगाई है। उन्होंने बताया कि कैप्टन शुभांशु शुक्ला अंतरराष्ट्रीय अंतरिक्ष स्टेशन (आईएसएस) तक पहुंचने वाले पहले भारतीय बने, जो देश के लिए ऐतिहासिक उपलब्धि है। यह सफलता भारत की वैज्ञानिक क्षमता और अंतरिक्ष अनुसंधान में बढ़ती भूमिका को दर्शाती है। वहीं देश की सुरक्षा मामले पर बोलते हुए पीएम मोदी ने कहा कि 'ऑपरेशन सिंदूर' 2025 की सबसे बड़ी उपलब्धियों में से एक रहा। इस अभियान ने पूरी दुनिया को यह स्पष्ट संदेश दिया कि भारत अपनी सुरक्षा से कोई समझौता नहीं करता। उन्होंने कहा कि इस दौरान देशभर में मां भारती के प्रति प्रेम और समर्पण की भावना देखने को मिली।

खेल के लिहाज से ऐतिहासिक रहा साल 2025

प्रधानमंत्री मोदी ने खेल जगत की उपलब्धियों को भी रेखांकित किया। उन्होंने कहा कि 2025 खेल के लिहाज से भी ऐतिहासिक रहा। पुरुष क्रिकेट टीम ने आईसीसी चैंपियंस ट्रॉफी जीती, जबकि महिला क्रिकेट टीम ने पहली बार विश्व कप अपने नाम किया। इसके अलावा भारत की बेटियों ने ब्लाइंड टी-20 वर्ल्ड कप जीतकर नया इतिहास रचा। पैरा एथलीटों ने भी विश्व चैंपियनशिप में शानदार प्रदर्शन करते हुए कई पदक हासिल किए।

चीतों की भारत में बढ़ी संख्या

पर्यावरण और वन्यजीव संरक्षण पर बात करते हुए पीएम मोदी ने कहा कि 2025 में इस दिशा में कई महत्वपूर्ण पहल शुरू हुईं। उन्होंने खुशी जताई कि भारत में चीतों की संख्या अब 30 से अधिक हो चुकी है, जो संरक्षण प्रयासों की सफलता को दर्शाता है।

संघ की प्रशंसा वाले बयान पर दिग्विजय सिंह के समर्थन में आए थरुर ने भी संघ की कर दी तारीफ

नई दिल्ली।

कांग्रेस के वरिष्ठ नेता दिग्विजय सिंह द्वारा राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ (आरएसएस) की संगठनात्मक क्षमता की सराहना किए जाने के बाद अब सांसद शशि थरूर ने भी उनकी बातों का समर्थन किया है। थरूर ने कहा कि कांग्रेस को भी अपने संगठन को मजबूत करने और उसमें अनुशासन बढ़ाने की आवश्यकता है। शशि थरूर ने प्रतिक्रिया देते हुए कहा कि किसी भी राजनीतिक दल के लिए अनुशासन और जमीनी स्तर पर मजबूती बेहद महत्वपूर्ण होती है। उन्होंने कहा, हमें संगठन की मजबूती और अनुशासन सीखना चाहिए। दिग्विजय सिंह जो कह रहे हैं, वह सही है। मैं भी यही चाहता हूँ कि हमारा संगठन और अधिक मजबूत और अनुशासित बने। थरूर ने आगे जोड़ा कि कांग्रेस का 140 वर्षों का गौरवशाली इतिहास है और पार्टी अपने अनुभवों से भी बहुत कुछ सीख सकती है, लेकिन वर्तमान समय में कार्यक्षमता बढ़ाने के लिए अनुशासन पर ध्यान देना अनिवार्य है। यह पूरा विवाद दिग्विजय सिंह के एक सोशल मीडिया पोस्ट से शुरू हुआ, जिसे उन्होंने कार्यसमिति की बैठक से ठीक पहले साझा किया था। सिंह ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की एक पुरानी तस्वीर साझा की थी, जिसमें वे लालकृष्ण आडवाणी के पास नीचे बैठे नजर आ रहे हैं। इस तस्वीर के साथ दिग्विजय सिंह ने लिखा था कि कैसे एक जमीनी स्वयंसेवक और कार्यकर्ता अपनी निष्ठा और संगठन की शक्ति के बल पर मुख्यमंत्री और प्रधानमंत्री के पद तक पहुँचा। दिग्विजय सिंह के इस बयान ने राजनीतिक गलियारों में हलचल पैदा कर दी है। जहाँ कुछ लोग इसे आत्मनिरीक्षण की दृष्टि से देख रहे हैं, वहीं थरूर के समर्थन ने इस चर्चा को और हवा दे दी है कि कांग्रेस के भीतर अब संगठन के ढांचे और कार्यशैली में बड़े बदलावों की जरूरत महसूस की जा रही है।

कांग्रेस ने कभी धर्म के नाम पर वोट नहीं मांगा, कांग्रेस जोड़ती है और बीजेपी तोड़ती है

-कांग्रेस के स्थापना दिवस पर खड़गे ने बीजेपी और आरएसएस पर साधा निशाना

नई दिल्ली।

कांग्रेस के स्थापना दिवस पर रविवार को पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे और संसदीय दल की अध्यक्ष सोनिया गांधी ने वरिष्ठ नेताओं की मौजूदगी में झंडा फहराया। इस मौके पर मल्लिकार्जुन खड़गे ने बीजेपी और आरएसएस पर निशाना साधते हुए गंभीर आरोप लगाए। उन्होंने कांग्रेस को खत्म करने की बात करने वालों को चुनौती दी। उन्होंने कहा कि हमें साथ मिलकर कांग्रेस की सोच और विचारधारा को जन-जन तक पहुंचाना है। सभी को सामाजिक न्याय दिलाकर, खुशहाल हिंदुस्तान बनाना है।

खड़गे ने कहा कि 28 दिसंबर 1885 को मुंबई में कांग्रेस की स्थापना हुई थी। तब से 62 साल तक करोड़ों कांग्रेसजनों ने अंग्रेजों से संघर्ष किया, त्याग और बलिदान दिया, जेल में यातनाएं झेली, तब जाकर देश आजाद हुआ। उन्होंने कहा कि मैं कांग्रेस के सभी निर्माताओं और स्वाधीनता सेनानियों को श्रद्धांजलि देता हूं। संविधान और मजबूत लोकतंत्र की स्थापना करने वाले नायकों को नमन करते हुए कहना चाहता हूं कि उनके सपनों के भारत के लिए कांग्रेस हर संभव प्रयास करती रहेगी। आजादी के पहले कांग्रेस ने मौलिक अधिकारों का जो स्वरूप बनाया था, वह हमारे संविधान का हिस्सा बना, लेकिन आज संविधान और लोकतंत्र दोनों खतरे में हैं।

खड़गे ने कहा कि जो कहते हैं- कांग्रेस खत्म हो गई है उन्हें मैं बताना चाहता हूं- हमारे पास सत्ता कम हो सकती है, लेकिन हमारी रीढ़ अभी भी सीधी है। हमने समझौता नहीं किया, न संविधान से, न धर्मनिरपेक्षता से, न गरीबों के हकों से। हम सत्ता में ना हों, लेकिन सौदेबाजी नहीं करेंगे। कांग्रेस ने कभी धर्म के नाम पर वोट नहीं मांगा, कांग्रेस ने कभी मंदिर-मस्जिद पर नफरत नहीं फैलाई। कांग्रेस जोड़ती है और बीजेपी तोड़ती है।

उन्होंने कहा कि कांग्रेस ने धर्म को आस्था ही रखा, लेकिन कुछ लोगों ने धर्म को राजनीति बना दिया। आज बीजेपी के पास सत्ता है, लेकिन उनके पास सच्चाई नहीं है। इसीलिए कभी आंकड़े छिपाए जाते हैं, कभी जनगणना रोकी जाती है, कभी संविधान बदलने की बातें होती हैं।

नए साल के स्वागत के लिए दिल्ली तैयार.....20,000 जवान पर रहेगी सुरक्षा की जिम्मेदारी

नई दिल्ली। नए साल के स्वागत के लिए दिल्ली पूरी तरह तैयार है, लेकिन इस दौरान सुरक्षा और कानून-व्यवस्था बनाए रखने के लिए दिल्ली पुलिस ने विशेष तैयारी की हैं। पुलिस अधिकारियों ने बताया कि शराब पीकर गाड़ी चलाने और यातायात नियमों का उल्लंघन करने वालों पर इस बार कड़ी नजर रहेगी। नए साल की पूर्व संध्या पर दिल्ली की सड़कों, बाजारों और मॉल के आसपास दिल्ली पुलिस, ट्रैफिक पुलिस और अर्धसैनिक बलों के लगभग 20,000 जवान तैनात रहने वाले है। हरियाणा और उत्तर प्रदेश से आने वाली भीड़ को देखते हुए दिल्ली की सीमाओं पर सुरक्षा बढ़ा दी गई है। प्रवेश द्वारों पर हर वाहन की जांच होगी। कनॉट प्लेस, हौज खास और प्रमुख शॉपिंग मॉल्स के आसपास विशेष नाकेबंदी की गई है। रणनीतिक स्थानों पर त्वरित प्रतिक्रिया टीमें (क्यूआरटी) तैनात रहेंगी। ट्रैफिक पुलिस ने खतरनाक ड्राइविंग और स्टंटबाजी रोकने के लिए सख्त योजना तैयार की है। शराब पीकर गाड़ी चलाने वालों की पहचान के लिए पुलिस बड़े पैमाने पर ब्रेथ एनालाइजर का उपयोग करेगी।

दिल्ली में सक्रिय 35 हजार नकली डॉक्टर..... कार्रवाई के नाम पर एक पर ही एफआईआर दर्ज

नई दिल्ली।

देश की राजधानी दिल्ली में बिना डिग्री और मेडिकल पढ़ाई के लोगों का इलाज कर रहे नकली डॉक्टरों के खिलाफ कार्रवाई के मामले में दिल्ली मेडिकल काउंसिल (डीएमसी) के उदासीन रवैये का खुलासा हुआ है।

बीते दो सालों में दिल्ली में केवल एक नकली डॉक्टर के खिलाफ एफआईआर दर्ज की गई है, जबकि राजधानी में हजारों की संख्या में इसतरह के लोग गलत इलाज कर लोगों की जान से खिलवाड़ कर रहे हैं। रिपोर्ट के अनुसार, साल 2024 में 9 मामलों की जांच की गई, लेकिन एक भी मामले में एफआईआर दर्ज नहीं हुई।

इसकी वजह यह रही कि डीएमसी की ओर से एक भी केस पुलिस को एफआईआर दर्ज कराने के लिए नहीं भेजा गया। वहीं, 2025 में अब तक 22 मामलों की जांच हुई, लेकिन केवल एक केस पुलिस को भेजा गया, जिस पर एफआईआर दर्ज की गई। पिछले पांच सालों में दिल्ली में नकली डॉक्टरों के खिलाफ कुल 22 एफआईआर दर्ज हो सकी है।

इस बारे में दिल्ली मेडिकल काउंसिल के एंटी क्रैकरी सेल के अधिकारी ने कहा कि साल 2015 में दिल्ली हाई कोर्ट ने आदेश जारी कर एक कमिटी बनाई थी, जिसे हर महीने दिल्ली में छापेमारी करनी थी। हालांकि, यह रिपोर्ट साफ दिखा रही है कि आदेशों का सही तरीके से पालन नहीं हो रहा है।

अनुमान के मुताबिक, दिल्ली में 35 से 40 हजार नकली डॉक्टर सक्रिय हैं, जो इलाज के नाम पर आम जनता को ठग रहे हैं। कई बार गरीब मरीजों को इसकी कीमत अपनी जान देकर चुकानी पड़ती है।

हादी की मौत की जिम्मेदार ISI-DGFI!

- **पूर्व रॉ एजेंट के दावों से बढ़ा बांग्लादेश-पाकिस्तान विवाद**
- **बांग्लादेश-पाकिस्तान कटघरे में, बांग्लादेश की राजनीति में उबाल**
- **ऑडियो बम से हिली दक्षिण एशिया की सियासत**
- **पूर्व रॉ एजेंट को भयानक मौत की धमकी**

नई दिल्ली/ढाका ।

बांग्लादेश में शरीफ उस्मान हादी की रहस्यमयी मौत और उसके बाद भड़की हिंसा को लेकर अब अंतरराष्ट्रीय स्तर पर नया विवाद खड़ा हो गया है। भारत के पूर्व रॉ एजेंट लक्की बिष्ट द्वारा सोशल मीडिया पर साझा किए गए एक कथित ऑडियो क्लिप ने दक्षिण एशिया की राजनीति और खुफिया गलियारों में हलचल मचा दी है।

लक्की बिष्ट का दावा है कि इस ऑडियो में बांग्लादेश के एक वरिष्ठ अधिकारी की आवाज़ है, जिसमें साफ तौर पर कहा गया है कि शरीफ उस्मान हादी की हत्या के पीछे पाकिस्तान की खुफिया एजेंसी आईएसआई और यूसुफ़ खान की भूमिका थी। बिष्ट के अनुसार, इस साजिश को बांग्लादेश की खुफिया एजेंसी डीजीएफआई की कथित मौन सहमति भी प्राप्त थी। हालांकि, इस ऑडियो की आधिकारिक पुष्टि अब तक किसी भी एजेंसी द्वारा नहीं की गई है।

पूर्व रॉ अधिकारी लक्की बिष्ट ने दावा किया है कि ऑडियो सार्वजनिक करने के बाद उन्हें ई-मेल, सोशल मीडिया और अन्य डिजिटल माध्यमों से लगातार जान से मारने की धमकियां मिल रही हैं। बिष्ट के अनुसार, इन संदेशों में कथित तौर पर डीजीएफआई और आईएसआई से जुड़े नेटवर्क का हवाला दिया गया है और उन्हें ऐसी ÷भयानक मौत÷ देने की चेतावनी दी गई है, जिसकी उन्होंने कभी कल्पना भी नहीं की होगी।

लक्की बिष्ट का आरोप है कि पाकिस्तान और बांग्लादेश की खुफिया एजेंसियां मिलकर इस मामले की सच्चाई को दबाने की कोशिश कर रही हैं, क्योंकि अगर शरीफ उस्मान हादी की मौत के पीछे की वास्तविक वजह सामने आती है, तो दोनों देशों की अंतरराष्ट्रीय छवि को गंभीर नुकसान पहुंच सकता है।

इस कथित खुलासे के बाद बांग्लादेश में राजनीतिक माहौल भी गर्म हो गया है।

उमर हान नामक व्यक्ति ने सार्वजनिक रूप से यूनूस सरकार को चुनौती देते हुए हादी की मौत और उसके बाद हुई हिंसा के लिए सीधे सरकार को जिम्मेदार ठहराया है। इससे पहले ही बांग्लादेश में हालात संवेदनशील बने हुए थे, और अब इन आरोपों ने सरकार की भूमिका पर नए सवाल खड़े कर दिए हैं।

Web site : www.krantisamay.com & epaper.krantisamay.com www.facebook.com/krantisamay1 www.twitter.com/krantisamay1

संख्या की जीत, जीवन की हारः टाइगर संरक्षण की सफलता कैसे बन गई सबसे बड़ी चुनौती

संरक्षण की इस विडंबना का एक बड़ा कारण यह है कि हम सफलता को केवल संख्या के चश्मे से देखने लगे हैं। हर नई रिपोर्ट में बाघों की गिनती बढ़ने पर तालियां बजाई जाती हैं, लेकिन यह नहीं देखा जाता कि वे बाघ किस हालात में जी रहे हैं। बिना समानांतर आवास विस्तार, कॉरिडॉर संरक्षण और वैज्ञानिक प्रबंधन के केवल संख्या बढ़ना खुद बाघों के लिए जानलेवा साबित हो रहा है। यह वही स्थिति है जैसे किसी कमरे में लोगों की संख्या लगातार बढ़ती जाए, लेकिन कमरे का आकार वही रहे। कुछ समय बाद टकराव, तनाव और दुर्घटनाएं अपरिहार्य हो जाती हैं।

(लेखक - कांतिलाल मांडोत)

भारत में बाघ संरक्षण को बीते एक दशक की सबसे बड़ी पर्यावरणीय सफलता के रूप में प्रस्तुत किया जाता रहा है। हर नई गणना के साथ बाघों की बढ़ती संख्या राष्ट्रीय गर्व का विषय बनी। अंतरराष्ट्रीय मंचों पर भारत को टाइगर स्टेटके रूप में सराहा गया। लेकिन अब यही सफलता एक गहरी और खामोश चुनौती में बदलती दिख रही है। बाघ बढ़े हैं, पर उनके ठिकाने सिमट गए हैं। जंगल कागजों में सुरक्षित हैं, पर व्यवहारिक रूप से बाघों के लिए सांस लेने की जगह कम होती जा रही है। नतीजा यह है कि टाइगर रिजर्व अब संरक्षण के सुरक्षित दुर्ग नहीं, बल्कि टकराव के मैदान बनते जा रहे हैं।

पिछले पांच वर्षों में 721 बाघों की मौत इस बात का सबसे ठोस और भयावह संकेत है कि संरक्षण की मौजूदा रणनीति अपने ही बोझ तले दब रही है। अकेले वर्ष 2025 में अब तक 162 बाघों की मौत हो चुकी है, जो 2023 के बाद सबसे अधिक है। यह आंकड़ा किसी प्राकृतिक आपदा का नहीं, बल्कि मानव निर्मित नीति संकट का परिणाम है। मध्यप्रदेश, जिसे टाइगर स्टेट कहा जाता है, इन मौतों में सबसे आगे है। यहां 55 बाघों की मौत दर्ज की गई। महाराष्ट्र में 36, राजस्थान और छत्तीसगढ़ में दो-दो बाघों की मौत ने साफ कर दिया है कि यह समस्या किसी एक राज्य या एक रिजर्व तक सीमित नहीं रही।

बाघों की मौत के कारणों पर नजर डालें तो तस्वीर और भी चिंताजनक हो जाती है। आपसी संघर्ष, क्षेत्र को लेकर हिंसा, मानव-वन्यजीव टकराव, बीमारी और अवैध गतिविधियां।ये सभी कारण मिलकर एक ऐसे संकट को जन्म दे रहे हैं, जिसे अब नजरअंदाज करना संभव नहीं। बाघ एक एकांतप्रिय और विशाल क्षेत्र में विचरण करने वाला जीव है। जब उसकी संख्या बढ़ती है और क्षेत्र वही रहता है, तो संघर्ष अनिवार्य हो जाता है। युवा बाघों के लिए नए इलाके नहीं बचते, वे या तो वरिष्ठ बाघों से लड़ते हैं या जंगल से बाहर निकलकर मानव बस्तियों की ओर बढ़ते हैं। दोनों ही स्थितियां अंततः मौत पर जाकर खत्म होती हैं।

यह कहना कि जंगल कम नहीं हुए, केवल आधा सच है। वन क्षेत्र का आंकड़ा स्थिर हो सकता है, लेकिन बाघों के उपयोग योग्य, सुरक्षित और आपस में जुड़े आवास लगातार घटे हैं। सड़कें, रेल लाइनें, खनन, बिजली परियोजनाएं और बढ़ता पर्यटन जंगलों को टुकड़ों में बांट चुका है। कॉरिडॉर टूट रहे हैं, जिनके सहारे बाघ एक रिजर्व से दूसरे रिजर्व तक सुरक्षित आवाजाही करते थे। परिणामस्वरूप, टाइगर रिजर्व अब द्वीपों की तरह अलग-थलग पड़ते जा रहे हैं, जहां बाघों की संख्या तो बढ़ रही है, लेकिन फैलने की जगह नहीं है।

आंकड़े इस संकट की निरंतरता को स्पष्ट करते हैं। वर्ष 2021 में 129 बाघों की मौत हुई, 2022 में 122, 2023 में यह संख्या बढ़कर 182 तक पहुंच गई, 2024 में 126 और 2025 में अब तक 162 मौतें दर्ज की जा चुकी हैं। इनमें से शिकार के मामलों में तीन वर्षों के भीतर 36 बाघों की जान गई, जो यह बताने के लिए पर्याप्त है कि अवैध गतिविधियां अब भी पूरी तरह काबू में नहीं हैं। इससे भी अधिक चिंता की बात यह है कि जांच की प्रक्रिया बेहद धीमी है। राष्ट्रीय बाघ संरक्षण प्राधिकरण के रिकॉर्ड के अनुसार 2012 से 2024 के बीच कुल बाघ मौतों के लगभग 29 प्रतिशत मामलों की जांच अब भी लंबित है। इनमें 407 मामले पिछले पांच वर्षों के हैं। जब मौत के कारणों की स्पष्ट जांच ही समय पर नहीं हो पा रही, तो नीतिगत सुधार कैसे होंगे, यह सवाल अपने आप खड़ा होता है।

संरक्षण की इस विडंबना का एक बड़ा कारण यह है कि हम सफलता को केवल संख्या के चश्मे से देखने लगे हैं। हर नई रिपोर्ट में बाघों की गिनती बढ़ने पर तालियां बजाई जाती हैं, लेकिन यह नहीं देखा जाता कि वे बाघ किस हालात में जी रहे हैं। बिना समानांतर आवास विस्तार, कॉरिडॉर संरक्षण और वैज्ञानिक प्रबंधन के केवल संख्या बढ़ना खुद बाघों के लिए जानलेवा साबित हो रहा है। यह वही स्थिति है जैसे किसी कमरे में लोगों की संख्या लगातार बढ़ती जाए, लेकिन कमरे का आकार वही रहे। कुछ समय बाद टकराव, तनाव और दुर्घटनाएं अपरिहार्य हो जाती हैं।

विशेषज्ञ लंबे समय से अतिरिक्त बाघों को नए और उपयुक्त आवासों में स्थानांतरित करने की जरूरत पर जोर दे रहे हैं। टाइगर शिफ्टिंग प्रोजेक्ट एक व्यवहारिक समाधान हो सकता है, जिसके तहत भीड़भाड़ वाले रिजर्व से बाघों को उन क्षेत्रों में बसाया जाए, जहां अभी उपयुक्त आवास तो है, लेकिन बाघों की संख्या कम या शून्य है। देश में ऐसे कई संभावित परिदृश्य मौजूद हैं। लेकिन जमीनी स्तर पर इस दिशा में ठोस पहल दिखाई नहीं देती। योजनाएं फाइलों में कैद हैं और निर्णय राजनीतिक, प्रशासनिक और आर्थिक हितों के जाल में उलझे हुए हैं।

इस संकट में पर्यटन बनाम संरक्षण की बहस भी तेजी से उभरकर सामने आ रही है। टाइगर रिजर्व के आसपास बढ़ता रिसॉर्ट उद्योग नीति निर्धारण पर असर डाल रहा है। पर्यटन से होने वाली आय ने कई बार संरक्षण की प्राथमिकताओं को पीछे धकेल दिया है। जंगलों के कोर और बफर क्षेत्रों में मानव गतिविधियां बढ़ रही हैं, जिससे बाघों का स्वाभाविक व्यवहार प्रभावित हो रहा है। नए क्षेत्रों में संरक्षण विस्तार की योजनाएं इसलिए भी ठंडी पड़ जाती हैं, क्योंकि पर्यटन की मौजूदा संरचना को खतरा महसूस होने लगता है। बाघ अब केवल एक वन्यजीव नहीं, बल्कि एक आर्थिक संसाधन के रूप में देखा जाने लगा है, और यही सोच संरक्षण के मूल उद्देश्य से टकरा रही है।

मानव-वन्यजीव टकराव इस पूरे संकट का सबसे संवेदनशील पहलू है। जब बाघ जंगल से बाहर निकलते हैं, तो वे केवल अपने लिए जगह तलाश रहे होते हैं, लेकिन मानव समाज उन्हें खतरे के रूप में देखता है। खेतों में मवेशियों का शिकार, कभी-कभी इंसानी जान का नुकसान, और उसके बाद बदले की भावना।यह चक्र लगातार तेज होता जा रहा है। ऐसे मामलों में अक्सर बाघ को ही दोषी ठहराया जाता है, जबकि असल दोष उस व्यवस्था का होता है, जिसने उसके रहने की जगह छीनी।

अब समय आ गया है कि टाइगर संरक्षण की रणनीति पर नए सिरे से विचार किया जाए। केवल गिनती बढ़ाने की होड़ से बाहर निकलकर गुणवत्ता आधारित संरक्षण मॉडल अपनाने की जरूरत है। इसमें बड़े और जुड़े हुए आवासों का विकास, कॉरिडॉर की कानूनी सुरक्षा, वैज्ञानिक आधार पर बाघों का स्थानांतरण, स्थानीय समुदायों की भागीदारी और पर्यटन की स्पष्ट सीमाएं तय करना शामिल होना चाहिए। जांच प्रक्रियाओं को तेज और पारदर्शी बनाना भी उतना ही जरूरी है, ताकि हर मौत से सबक लिया जा सके, न कि उसे केवल एक और आंकड़े में बदल दिया जाए।

बाघ भारत की जैव विविधता का प्रतीक है। उसकी दहाड़ जंगलों की सेहत का संकेत मानी जाती है। लेकिन अगर यह दहाड़ अब टकराव और मौत की आवाज में बदलती जा रही है, तो यह पूरे संरक्षण मॉडल पर सवाल है। संख्या की जीत अगर जीवन की हार में बदल जाए, तो ऐसी सफलता पर पुनर्विचार जरूरी है। बाघों को बचाने का मतलब केवल उन्हें गिनना नहीं, बल्कि उन्हें वह जगह देना है, जहां वे बिना टकराव, बिना डर और बिना मौत के खतरे के जी सकें। यही असली संरक्षण होगा, और यही भविष्य की सबसे बड़ी जरूरत ।

(वरिष्ठ पत्रकार, साहित्यकार, स्तम्भकार)

(यह लेखक के व्य क्तिगत विचार हैं इससे संपादक का सहमत होना अ निवार्य नहीं है)

संपादकीय

डिजिटल अरेस्ट स्कैम

शायद ही कोई दिन ऐसा जाता होगा जब कोई बुजुर्ग या आम लोग साइबर ठगी के शिकार न हुए हों। पिछले दिनों महाराष्ट्र में एक सेवानिवृत्त जज भी डिजिटल अरेस्ट स्कैम के शिकार हो गए। पिछले सप्ताह ऐसा ही एक अन्य दुखद मामला पुणे से सामने आया जब साइबरों ठगों ने एक 82 वर्षीय सेवानिवृत्त अधिकारी को डिजिटल हाउस अरेस्ट स्कैम में फंसाकर 1.19 करोड़ लूट लिए। कई दिन के मानसिक उत्पीड़न व आर्थिक क्षति से टूट गए वृद्ध की आखिर सदमे से मौत हो गई। यह विचारणीय पहलू है कि कैसे पढ़े-लिखे लोग साइबर ठगों की साजिश की गिरफ्त में आ जाते हैं। वैसे आम आदमी को साइबर ठगों व फर्जी फोन कॉल्स से बचाने के लिये पुख्ता व्यवस्था होना बेहद जरूरी है। आम लोगों की सुविधा व सुरक्षा के लिये सरकार के प्रयासों के बाद अब दूरसंचार विभाग ने मार्च 2026 में ऐसी व्यवस्था लागू करने के तैयारी की, जिसमें बिना टू-कॉलर के खुद मोबाइल अवांछित फोन के प्रति सजग करेगा। नियामक संस्था ट्राई ने इस प्रस्ताव पर सहमति जतायी है। यह विडंबना ही कि जैसे-जैसे नई तकनीक आम आदमी के जीवन में सुविधा लाती है, वहीं असामाजिक तत्व उसे लूट-खसोट का हथियार बनाने में आगे निकल जाते हैं। देश में इंटरनेट सेवाओं के विस्तार और मोबाइल फोन की संख्या में अप्रत्याशित वृद्धि के साथ ही साइबर अपराधों में खासी तेजी आई है। जरा सी चूक होने पर लाखों लोग, साइबर धोखाधड़ी में अपने जीवनभर की पूंजी कुछ ही क्षणों में गवां देते हैं। अपराधियों का संजाल इतना विस्तृत व रहस्यमय है कि प्रवर्तन एजेंसियां जब तक उन तक पहुंचती हैं, पैसा विदेशों में ट्रांसफर हो जाता है। इस संकट का एक पहलू अनजान नंबरों से आने वाली फोन कॉल्स होती हैं, जिसके जरिये अपराधी लोगों को भ्रमित कर जीवन की जमा पूंजी लूट लेते हैं। दरअसल, संचार क्रांति के चलते तमाम सेवाएं ऑनलाइन उपलब्ध हुई हैं, लेकिन इस सुविधा के साथ पुरानी पीढ़ी साम्य नहीं बैठा पाती है। अब इसी चुनौती को दूर करने के लिये दूरसंचार विभाग आम उपभोक्ता को ऐसी सुविधा देने जा रहा है, जिसमें फोन करने वाले को पहचाना जा सकेगा। फोन पर कॉल करने वाले व्यक्ति का नाम लिखा नजर आएगा। फिर व्यक्ति अपनी सुविधा अनुसार फोन कॉल्स लेना तय कर सकता है। दूरसंचार नियामक ट्राई की मंजूरी के बाद इस दिशा में तेजी से काम हो रहा है। हालांकि, फोन करने वाले व्यक्ति की जानकारी जुटाने के कई ऐप अभी भी मौजूद हैं, लेकिन उनका उपयोग कुछ ही लोग कर पाते हैं। वैसे ऐसा निश्चित रूप से नहीं कहा जा सकता कि ऐप द्वारा दी जाने वाली सूचना सटीक है। ऐसे में यदि दूरसंचार विभाग की कोशिश सिरे चढ़ती है तो इससे करोड़ों उपभोक्ताओं को सुरक्षा कवच मिल पाएगा। पहले इस सुविधा का लेना मांग पर आधारित था, लेकिन बाद में तय किया गया कि यह सुविधा प्रत्येक मोबाइल उपयोगकर्ता को उपलब्ध करायी जाएगी। विश्वास किया जा रहा है कि अगले साल मार्च तक पूरे देश में यह सुविधा उपलब्ध हो जाएगी। जानकारों का मानना है कि इस सुविधा से किसी सीमा तक मोबाइल के जरिये धोखाधड़ी करने वाले अपराधियों पर नकेल कसी जा सकेगी। मोबाइल उपयोगकर्ता की सजगता इसमें मददगार हो सकेगी। स्क्रीन पर अनजान नंबर व नाम देखने के बाद मोबाइलधारक फोन कॉल्स को उठाने से बच सकता है। वैसे इसके साथ ही देश में डिजिटल साक्षरता की दिशा में व्यापक पहल करने की जरूरत है। विभिन्न सूचना माध्यमों के जरिये लोगों को सजग-सतर्क किए जाने की आवश्यकता है।

उपलब्धियो और खामियों के बीच जूझता रहा 2025!

(लेखक- डॉ श्रीगोपाल नारसन)

बीत रहा सन 2025 का साल भारत के लिए रक्षा, प्रौद्योगिकी, खेल और अर्थव्यवस्था के क्षेत्र में उपलब्धियों भरा रहा।इस बीत रहे वर्ष में स्वदेशी स्टील्थ फ्रिगेट लॉन्च हुए, अग्नि प्राइम का सफल परीक्षण हुआ, महिला क्रिकेट ने वर्ल्ड कप जीता, और विकसित भारत बिल्डथॉन जैसी पहल हुईं,साथ ही एआई में उभरती शक्ति के रूप में पहचान मिली, जबकि इलेक्ट्रॉनिक्स और ईवी जैसे सेक्टर में वृद्धि देखी गई, लेकिन यह साल कुछ राजनीतिक उथल-पुथल और भारत-पाकिस्तान के बीच तनावपूर्ण ऑपरेशन सिंदूर के संघर्ष का साक्षी भीरहा।सन 2025 में कई क्षेत्रों में निराशाएँ देखने को मिलीं, खासकर भारतीय फुटबॉल में प्रशासनिक संकट और खराब प्रदर्शन, भारतीय एयरलाइंस सेक्टर में अनिश्चितता, युवाओं के बीच नौकरी को लेकर चिंताएँ, और डिजिटल युग में निजता व सुरक्षा के मुद्दे, तथा कुछ चर्चित किताबों का उम्मीदों के मुताबिक न आना प्रमुख कहे जा सकते है।2025 भी हर साल की तरह राजनीतिक घटनाओं से भरा रहा, और देश भर में विवाद और बहस हुई. सबसे बड़ा वाकया तो इस लिहाज से ऑपरेशन सिंदूर रहा, जब पूरा देश एकजुट नजर आया. क्या सत्ता पक्ष और क्या विपक्ष, अगर सीजफायर पर आरोप-प्रत्यारोप को दरकिनार कर दें तो जिस तरह सभी दलों के सांसदों की अलग-अलग टीम बनाकर दुनिया में भारत का पक्ष समझाने के लिए भेजी गई, उसने अनूठी मिसाल पेश की।जगदीप धनखड़ का उपराष्ट्रपति पद से अचानक इस्तीफा और वोट चोरी के आरोपों के बीच चुनाव आयोग की तरफ से स्क्रूक्रयानी विशेष गहन पुनरीक्षण कराए जाने को लेकर भी खासा विवाद हुआ. कांग्रेस नेता राहुल गांधी तो स्क्रूक्रके बहाने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के खिलाफ, वोट चोर, गद्दी छोड़ मुहिम ही चलाने लगे हैं. 2025 में देश की न्यायपालिका भी कुछ घटनाओं और विवादों की वजह से सुर्खियों का हिस्सा बनी।जम्मू-कश्मीर में 22 अप्रैल के पहलगाम आतंकवादी हमले के खिलाफ ऑपरेशन सिंदूर शुरू किया गया। ऑपरेशन सिंदूर में सरहद पार पाकिस्तान में बने कई आतंकवादी ठिकानों को नेस्तनाबूद किया गया और 125 से ज्यादा आतंकवादी मारे गए।

6 और 7 फरवरी की रात ऑपरेशन सिंदूर शुरू किया गया, और बाद में पाकिस्तान के साथ बातचीत के बाद सीजफायर लागू कर दिया गया।अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप का सीजफायर के लिए बीच बचाव का दावा रहा है, जिसे भारत सरकार ने सिरे से खारिज कर दिया है।

ट्रंप के दावे पर भारत में भी खूब राजनीति हुई।विपक्षी गठबंधन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और केंद्र सरकार से सीजफायर के मामले में जवाब मांगता रहा, और चर्चा के लिए संसद का विशेष सत्र बुलाने की मांग भी होती रही। विशेष सत्र तो नहीं बुलाया गया, लेकिन सत्र शुरू हुआ तो उसमें चर्चा जरूर हुई।बिहार चुनाव में नीतीश कुमार की सत्ता में वापसी से भी महत्वपूर्ण रहा विपक्षी राष्ट्रीय जनता दल का महज 25 सीटों पर सिमट जाना. बिहार चुनाव के नतीजों ने 2014 के लोकसभा चुनाव की याद दिला दी. हालांकि, तेजस्वी यादव की आरजेडी को इतनी सीटें जरूर मिल गईं, जिससे नेता प्रतिपक्ष का पद मिल सके।2025 के दिल्ली विधानसभा चुनाव में सत्ता परिवर्तन हो गया।आम आदमी पार्टी को शिकस्त देकर भारतीय जनता पार्टी दिल्ली में भी सत्ता पर काबिज हो गई, और रेखा गुप्ता मुख्यमंत्री बन गईं।अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने दुनिया के कई देशों पर टैरिफ लगाया।लेकिन, भारत का मामला थोड़ा अलग रहा। ऑपरेशन सिंदूर में सीजफायर कराने के उनके दावे को खारिज किए जाने के बाद 27 अगस्त से भारत पर ट्रंप प्रशासन ने टैरिफ बढ़ाकर 50 फीसदी कर दिया। यह कहकर कि सजा है रूसी तेल आयात करने की, जिससे पुतिन को यूक्रेन के खिलाफ युद्ध लड़ने के लिए पैसा मिल रहा है। ट्रंप टैरिफ के बाद विपक्ष ने मोदी-ट्रंप दोस्ती को मुद्दा बनाकर बीजेपी सरकार की विदेश नीति पर हमला किया।चाहे इंडिगो एयरलाइंस से जुड़ी अव्यवस्था हो, वायु प्रदूषण को लेकर बढ़ता गुस्सा हो, भाजपा शासित राज्यों में बढ़ता भ्रष्टाचार हो या गिरता रुपया, मोदी सरकार अपनी ही अक्षमता में फंसी दिख रही है और रोजमर्रा के शासन की चुनौतियों से निपटने में जूझ रही है।अर्थव्यवस्था की लगातार सुस्ती भी मोदी के सपने के टूटने की एक बड़ी वजह है। निजी निवेश में काफी गिरावट आई है और प्रत्यक्ष विदेशी निवेश भी कम हुआ है। अंतरराष्ट्रीय मुद्रा कोष ने हाल ही में मोदी सरकार के विकास आंकड़ों की सटीकता पर सवाल उठाए हैं।भारतीय देश छोड़कर जा रहे हैं।पिछले पांच वर्षों में करीब 10 लाख लोगों ने भारतीय नागरिकता छोड़ दी है।पहलगाम और दिल्ली के लाल किले में हुए आतंकी हमलों ने गृह मंत्री अमित शाह के उस दावे को गलत साबित कर दिया कि सीमा पार आतंकवाद की कमर तोड़ दी गई है।पहलगाम और दिल्ली में सुरक्षा की गंभीर चूक, खासकर यह तथ्य कि विस्फोटकों से भरी एक कार राष्ट्रीय राजधानी तक आसानी से पहुंच गई, ने चरमपंथ और उग्रवाद पर सख्ती से कार्रवाई करने वाली तथाकथित मजबूत सरकार की छवि को पूरी तरह ध्वस्त कर दिया है।

(लेखक राजनीतिक चिंतक व वरिष्ठ पत्रकार है)

चिंतन मनन

बद्ध होने का परिणाम

प्रकृति द्वारा बद्ध किए गए जीव कई प्रकार के होते है। कोई सुखी है और कोई अत्यंत कर्मठ है, तो दूसरा असहाय है। इस प्रकार के मनोभाव ही प्रकृति में जीव की बद्धावस्था के कारणस्वरूप हैं। भगवद्गीता के इस अध्याय में इसका वर्णन हुआ है कि वे किस प्रकार भिन्न-भिन्न प्रकार से बद्ध है। सर्वप्रथम सतोगुण पर विचार किया गया है। इस जगत में सतोगुण विकसित करने का लाभ यह होता है कि मनुष्य अन्य बद्धजीवों की तुलना में अधिक चतुर हो जाता है। सतोगुणी पुरुष को भौतिक कष्ट उतना पीड़ित नहीं करते और उसमें भौतिक ज्ञान की प्रगति करने की सूझ होती है। इसका प्रतिनिधि ब्राह्मण है, जो सतोगुणी माना जाता है। सुख का यह भाव इस विचार के कारण है कि सतोगुण में पापकर्मो से प्राय- मुक्त रहा जाता है। वास्तव में वैदिक साहित्य में यह कहा गया है कि सतोगुण का अर्थ ही है अधिक ज्ञान तथा सुख का अधिकाधिक अनुभव। सारी कठिनाई यह है कि जब मनुष्य सतोगुण में स्थित होता है, तो उसे ऐसा अनुभव होता है कि वह ज्ञान में आगे है और अन्यों की अपेक्षा श्रेष्ठ है। इस प्रकार वह बद्ध हो जाता है। इसके उदाहरण वैज्ञानिक तथा दार्शनिक हैं।

इनमें से प्रत्येक को अपने ज्ञान का गर्व रहता है और चूंकि वे अपने रहन-सहन को सुधार लेते है, अतएव उन्हें भौतिक सुख की अनुभूति होती है। बद्ध जीवन में अधिक सुख का यह भाव उन्हें भौतिक प्रकृति के गुणों से बांध देता है। अतएव वे सतोगुण में रहकर कर्म करने के प्रति आकृष्ट होते हैं। और जब तक इस प्रकार कर्म करते रहने का आकर्षर्ण बना रहता है, तब तक उन्हें किसी न किसी प्रकार का शरीर धारण करना होता है। इस प्रकार उनकी मुक्ति की कोई सम्भावना नहीं रह जाती। वे बारम्बार दार्शनिक, वैज्ञानिक या कवि बनते रहते हैं और बारम्बार जन्म-मृत्यु के उन्हीं दोषों में बंधते रहते हैं। लेकिन माया-मोह के कारण वे सोचते हैं कि इस प्रकार का जीवन आनंदप्रद है।

विचार मंथन

म्यांमार के चुनाव और भारत की दुविधा

(लेखक- सनत जैन)

म्यांमार में आखिरकार आम चुनाव के तहत रविवार को मतदान प्रक्रिया भी शुरु हो गई। इससे पहले भारत ने स्वतंत्र, निष्पक्ष और समावेशी लोकतांत्रिक प्रक्रिया के समर्थन में बयान जारी कर सुख और शांति की कामना की। कूटनीतिक तौर पर इस बयान को संतुलित बताया गया, लेकिन इसके निहितार्थ कहीं अधिक जटिल और चुनौतीपूर्ण नजर आते हैं। विदेश मंत्रालय का यह रुख ऐसे समय सामने आया है, जबकि म्यांमार गहरे राजनीतिक संकट से जुझते हुए गृहयुद्ध और अंतरराष्ट्रीय आलोचना के दौर से गुजर रहा है। यहां असल सवाल यही है, क्या मौजूदा परिस्थितियों में होने वाले आम चुनाव वास्तव में लोकतंत्र की बहाली का माध्यम बन सकते हैं, या फिर यह पूरी प्रक्रिया महज सैन्य शासन को वैधता देने का एक औजार भर हैं। ऐसे में भारत का आधिकारिक पक्ष स्पष्ट है, कि नई दिल्ली म्यांमार में शांति, स्थिरता और सामान्य स्थिति की वापसी चाहती है। लोकतांत्रिक बहाली का समर्थन भारत सदा से करता आया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा शंघाई सहयोग संगठन शिखर सम्मेलन के दौरान म्यांमार के सैन्य प्रमुख मिन आंग ह्लाइंग से मुलाकात और 'नेबरहुड फर्स्ट' तथा 'एक्ट ईस्ट' नीति के संदर्भ में म्यांमार को अहम बताना, भारत की व्यावहारिक विदेश नीति को दर्शाता है। भारत के लिए म्यांमार केवल एक पड़ोसी देश नहीं, बल्कि पूर्वोत्तर भारत की सुरक्षा, सीमा प्रबंधन, व्यापार और क्षेत्रीय संपर्क का एक महत्वपूर्ण कड़ी भी है। लेकिन यहीं से एक गंभीर और चुनौतिपूर्ण दुविधा का प्रारंभ भी नजर आता है। दरअसल 2021 में सैन्य तख्तापलट के बाद से म्यांमार में लोकतांत्रिक ढांचा लगभग ध्वस्त हो चुका है। आंग सान सू ची जैसी निर्वाचित नेता को जेल भेजा गया। उनकी लोकप्रिय पार्टी को भंग कर दिया गया और बड़े हिस्से में विद्रोही गुटों द्वारा नियंत्रण कर लिया गया। ऐसे में मौजूदा चुनाव की बात इसलिए भी अहम हो जाती है, क्योंकि इसमें न तो सभी राजनीतिक दल हिस्सा ले पा रहे हैं और न ही पूरा देश मतदान में हिस्सा लेने को तैयार नजर आया है। अत्याधिक पाबंदियों, भय और हिंसा के माहौल में मतदान की कछुआचाल इस बात का संकेत है कि आम जनता का भरोसा इस प्रक्रिया से उठ चुका है। खास बात तो यह भी है कि पश्चिमी देशों, संयुक्त राष्ट्र और मानवाधिकार संगठनों ने इन चुनावों की कड़ी आलोचना की है। उनका तर्क है कि यह चरणबद्ध चुनाव लोकतंत्र की बहाली नहीं, बल्कि सैन्य शासन द्वारा अपनी सत्ता को संस्थागत रूप देने की कोशिश है। सेना समर्थित यूनियन सॉलिडेरिटी एंड डेवलपमेंट पार्टी के जीतने की संभावना इस आशंका को और मजबूत करती है कि म्यांमार में 'लोकतंत्र' केवल नाम का होगा, जबकि वास्तविक शक्ति जुंटा के हाथों में ही रहेगी। भारत की स्थिति इसलिए भी संवेदनशील है क्योंकि वह खुलकर सैन्य शासन का समर्थन नहीं कर सकता, लेकिन पूरी तरह दूरी बनाना भी उसके रणनीतिक हितों के खिलाफ है। म्यांमार में अस्थिरता का सीधा असर भारत के पूर्वोत्तर राज्यों पर पड़ता है, फिर चाहे वह शरणार्थियों का मुद्दा हो, सीमा पार उग्रवाद हो या अवैध गतिविधियों का संचालन हो। इसीलिए भारत म्यांमार-नेतृत्व और म्यांमार-स्वामित्व वाली शांति प्रक्रिया पर जोर देता है और शांतिपूर्ण संवाद को ही समाधान मानता है। इस पूरे परिदृश्य में चीन की भूमिका एक निर्णायक के तौर पर उभरती दिखी है। विश्व स्तर पर विशेषज्ञ भी मानते हैं, कि म्यांमार के घटनाक्रमों में चीन का प्रभाव बढ़ता जा रहा है। बीजिंग द्वारा सशस्त्र समूहों पर दबाव, जुंटा को कूटनीतिक समर्थन और हथियारों की आपूर्ति यह संकेत देती है कि चीन इस चुनावी प्रक्रिया से रणनीतिक लाभ उठाना चाहता है। यदि म्यांमार पूरी तरह चीन के प्रभाव क्षेत्र में चला जाता है, तो यह भारत के लिए दीर्घकालिक भू-राजनीतिक चुनौती बन सकता है। ऐसे में भारत के सामने दोहरी जिम्मेदारी उभर कर आई है। एक ओर उसे लोकतांत्रिक मूल्यों और मानवाधिकारों के प्रति अपनी प्रतिबद्धता बनाए रखनी है, वहीं दूसरी ओर क्षेत्रीय स्थिरता और अपने रणनीतिक हितों की रक्षा भी करनी है। केवल चुनावों का समर्थन कर देना पर्याप्त नहीं है, बल्कि यह भी जरूरी है कि भारत समावेशिता, राजनीतिक संवाद और सभी हितधारकों की भागीदारी पर लगातार जोर देता रहे। म्यांमार का भविष्य केवल चुनावों से तय नहीं होगा, बल्कि स्वतंत्र लोकतांत्रिक सरकार का गठन के साथ ही चीन जैसी विदेशी ताकतों की दखलंदाजी का अंत भी मायने रखता है। इससे म्यांमार में वास्तविक राजनीतिक शांति के साथ ही हिंसा का अंत और जनता का विश्वास बहाल हो पाएगा।

Web site : www.krantisamay.com & epaper.krantisamay.com www.facebook.com/krantisamay1 www.twitter.com/krantisamay1

शीर्ष 10 में सात कंपनियों का बाजार पूंजीकरण 35,439 करोड़ घटा

- भारतीय स्टेट बैंक को सबसे अधिक नुकसान हुआ

नई दिल्ली । पिछले सप्ताह छुट्टियों के कारण थोड़ी हल्की कारोबार अवधि रही, लेकिन इस छोटे सप्ताह में शीर्ष 10 कंपे नियों में शामिल सात सबसे मूल्यवान कंपनियों का संयुक्त बाजार पूंजीकरण (मार्केट कैप) 35,439.36 करोड़ रुपये घट गया। इस दौरान भारतीय स्टेट बैंक (एसबीआई) को सबसे अधिक नुकसान हुआ। शीर्ष 10 में शामिल कंपनियों में रिलायंस इंडस्ट्रीज, टाटा कंसल्टेंसी सर्विसेज, आईसीआईसीआई बैंक, भारतीय स्टेट बैंक, बजाज फाइनेंस, लार्सन एंड टुब्रो और भारतीय जीवन बीमा निगम के बाजार पूंजीकरण में गिरावट आई। दूसरी ओर एचडीएफसी बैंक, भारती एयरटेल और इंफोसिस लाभ में रहे। भारतीय स्टेट बैंक का बाजार पूंजीकरण 12,692.1 करोड़ रुपये घटकर 8,92,046.88 करोड़ रुपये रह गया। रिलायंस इंडस्ट्रीज का मूल्यांकन 8,254.81 करोड़ रुपये घटकर 21,09,712.48 करोड़ रुपये पर आ गया। बजाज फाइनेंस के बाजार पूंजीकरण में 5,102.43 करोड़ रुपये की कमी आई और यह 6,22,124.01 करोड़ रुपये रह गया। दूसरी ओर एचडीएफसी बैंक का मूल्यांकन 10,126.81 करोड़ रुपये बढ़कर 15,26,765.44 करोड़ रुपये हो गया। इस दौरान इंफोसिस और भारती एयरटेल का मूल्यांकन भी बढ़ा। रिलायंस इंडस्ट्रीज सबसे मूल्यवान कंपनी बनी रही।

रिलायंस को नये साल में वित्तीय विवाद सुलझने की उम्मीद

नई दिल्ली । रिलायंस इंडस्ट्रीज ने बताया कि केजी डी6 ब्लॉक पर सरकार के साथ 24.7 करोड़ डॉलर के वित्तीय विवाद का मामला अंतरराष्ट्रीय मध्यस्थता के अंतिम चरण में है। कंपनी का कहना है कि सभी खर्च प्रबंधन समिति की मंजूरी के साथ किए गए और सरकार ने किसी अनियमितता का आरोप नहीं लगाया। सरकार का कहना है कि कुछ खर्च लागत वसूली में शामिल नहीं हैं और इस पर विंडफॉल टैक्स की मांग की जा रही है।रिलायंस के अनुसार नई खनन नीति में ऑपरेटर पहले अपनी लागत वसूल करता है, उसके बाद ही सरकार को लाभ मिलता है। परियोजना में सरकार ने कोई प्रत्यक्ष निवेश नहीं किया, जबकि ऑपरेटर ने मुख्य जोखिम उठाया। गैस की बिक्री कम दाम पर हुई, जिससे देश को सस्ती गैस मिली और सब्सिडी पर खर्च कम हुआ। विवाद का निर्णय 2026 में संभव है।

किसानों को जल्द मिलेगी पीएम किसान योजना की 22वीं किस्त

नई दिल्ली । प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना (पीएम-किसान) भारत के छोटे और सीमांत किसानों के लिए सबसे महत्वपूर्ण कल्याण योजनाओं में से एक है। इस योजना के तहत सरकार सीधे किसानों के बैंक खातों में वित्तीय सहायता भेजती है, जिससे बिचौलियों की भागीदारी खत्म होती है और पूरी पारदर्शिता सुनिश्चित होती है। देशभर के पात्र किसान अब 22वीं किस्त का बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं। हर किस्त में सरकार हजारों करोड़ रुपये जारी करती है, जो किसानों को कृषि में निवेश करने और जीवन यापन में मदद करती है। केंद्र सरकार प्रतिवर्ष इस योजना के लिए बजट आवंटित करती है। आगामी वित्तीय वर्ष का बजट 1 फरवरी 2026 को पेश किया जाएगा। कृषि मंत्रालय इस बजट में योजना के लिए नए निर्णय और संभावित वृद्धि की घोषणा कर सकता है। पीएम- किसान योजना देशभर के किसानों में अत्यधिक लोकप्रिय है और छोटे किसानों के लिए यह एक वरदान साबित हुई है। किसानों की नजर अब अगले बजट और 22वीं किस्त की तारीख पर टिकी हुई है।

इस सप्ताह निवेशकों की नजर अर्थव्यवस्था के आंकड़ों पर रहेगी

औद्योगिक उत्पादन से लेकर वाहन बिक्री तक, निवेशकों की गतिविधियों पर रहेगी नजर

मुंबई ।

देश के घरेलू शेयर बाजारों में पिछले सप्ताह तेजी देखने को मिली, लेकिन निवेशक अब अगले सप्ताह आने वाले आर्थिक आंकड़ों पर अपनी नजरें गड़ाएंगे। बाजार विशेषज्ञों का कहना है कि आने वाले सप्ताह में जारी होने वाले डेटा से शेयर बाजार की दिशा तय हो सकती है। आगामी सोमवार को औद्योगिक उत्पादन के आंकड़े जारी किए जाएंगे। यह आंकड़ा देश की विनिर्माण, खनन और उपयोगिता क्षेत्रों की गतिविधियों का महत्वपूर्ण संकेतक है। निवेशक और अर्थशास्त्री इसे अर्थव्यवस्था की स्वास्थ्य स्थिति जानने के लिए देखते हैं। उम्मीद से बेहतर आंकड़े बाजार में तेजी ला सकते हैं, जबकि कमजोर आंकड़े निवेशकों में सतर्कता पैदा कर सकते हैं। मंगलवार को औद्योगिक क्षेत्र का खरीद प्रबंधक सूचकांक (पीएमआई) जारी होगा। पीएमआई उद्योगों की उत्पादन क्षमता, नए ऑर्डर और रोजगार की स्थिति का संकेत देता है। यदि पीएमआई 50 से ऊपर रहेगा, तो इसे आर्थिक विस्तार का संकेत माना जाएगा, वहीं 50 से नीचे आने पर आर्थिक गतिविधियों में धीमापन का अनुमान लगाया जाएगा। सप्ताह के दौरान वाहनों की बिक्री के आंकड़े भी निवेशकों की नजर में रहेंगे। वाहन बिक्री में वृद्धि उपभोक्ता मांग और आर्थिक गतिविधियों की मजबूती को दर्शाती है। विशेषकर ऑटो और वित्तीय क्षेत्र के शेयरों पर इसका सकारात्मक असर देखने को मिल सकता है। विशेषज्ञों का मानना है कि पिछले सप्ताह की तेजी के बाद निवेशक इन आंकड़ों को ध्यान से देखेंगे। मजबूत आंकड़े बाजार में और बढ़त ला सकते हैं, जबकि कमजोर आंकड़े सतर्कता बढ़ा सकते हैं।

बैंक से लोन लेने पर 5 बातों का रखें ध्यान, नहीं होगा रिजेक्शन

- सिबिल स्कोर बना है लोन मिलने की सबसे बड़ी चाबी

नई दिल्ली । आज के समय में घर खरीदना हो, बच्चों की पढ़ाई या कोई बड़ी जरूरत, लोन लेना आम हो गया है। लेकिन कई बार बैंक में आवेदन करने के बाद भी लोन रिजेक्ट हो जाता है। इसकी सबसे बड़ी वजह खराब सिबिल स्कोर होता है। अगर आप भी बिना परेशानी लोन पाना चाहते हैं, तो इन पांच जरूरी बातों को जरूर अपनाएं-

- 1. 700 से ऊपर रखें सि बिल स्कोर- बैंक लोन देते समय सबसे पहले आपका क्रेडिट स्कोर देखते हैं। 300 से 900 के बीच आने वाले इस स्कोर में 700 से ऊपर का आंकड़ा सबसे सुरक्षित माना जाता है। अच्छा स्कोर बैंक का भरोसा बढ़ाता है।
- 2. ईएमआई समय पर चुकाना जरूरी- अगर होम लोन, पर्सनल लोन या क्रेडिट कार्ड की ईएमआई समय पर नहीं भरी जाती, तो इसका सीधा असरसिबिल स्कोर पर पड़ता है। नियमित भुगतान से स्कोर सुधरता है।
- 3. क्रेडिट कार्ड का सीमित उपयोग करें- क्रेडिट लिमिट का पूरा इस्तेमाल करने से बचें। बेहतर है कि 30 से 40 फीसदी लिमिट तक ही खर्च करें।
- 4. एक साथ कई लोन लेने से बचें- एक से ज्यादा लोन आपकी वित्तीय सेहत बिगाड़ सकते हैं। पहले पुराने कर्ज चुकाएं, फिर नया लोन लें।
- 5. जरूरत से ज्यादा कर्ज न लें- उतना ही लोन लें, जितना आसानी से चुका सकें और समय-समय पर अपनी क्रेडिट रिपोर्ट जांचते रहें।

तेल-तिलहन बाजार: सरसों में गिरावट, सोयाबीन और पामतेल में उछाल

- सरकार की पुरानी स्टॉक बिक्री और नई फसल की तैयारी के कारण बाजार में खरीदारी धीमी रही

नई दिल्ली ।

देश के तेल-तिलहन बाजार में बीते सप्ताह विविध रुझान देखने को मिले। सरसों तेल-तिलहन में गिरावट दर्ज की गई, जबकि सोयाबीन, पामतेल और पामोलीन तेल में सुधार आया। मूंगफली तेल-तिलहन स्थिर रहे और बिनौलातेल में हल्की वृद्धि देखी गई। विशेषज्ञों का कहना है कि यह स्थिति मौजूदा स्टॉक, एमएसपी, मांग और अंतरराष्ट्रीय सट्टेबाजी के मिश्रित प्रभाव का परिणाम है। बीते सप्ताह सरसों तेल-तिलहन के दाम में गिरावट रही। इसका मुख्य कारण पुरानी फसल की सरकारी बिक्री और स्टॉकिस्टों द्वारा बाजार में उतारा गया स्टॉक है। हाजिर दाम एमएसपी से 7-8 प्रतिशत अधिक है। नई फसल जल्द बाजार में आने वाली है, जिससे भाव पर दबाव बना रह सकता है। वहीं सोयाबीन तेल के दाम में पिछले सप्ताह की तुलना में सुधार आया। सर्दियों में डी-आयल्ड केक की मांग बढ़ी और सूरजमुखी तेल की तुलना में सोयाबीन तेल सस्ता होने के कारण स्थानीय खरीद बढ़ी। हालांकि एमएसपी के हिसाब से दाम अभी भी कमजोर हैं और बाजार एमएसपी पर नहीं खड़ा है। मूंगफली तेल-तिलहन के दाम स्थिर रहे। बिनौला तेल में हल्की वृद्धि देखी गई, मुख्य कारण हल्की मांग और नमकीन बनाने वाली कंपनियों की खरीद रही। बीते सप्ताह सरसों दाना 75 रुपये की गिरावट के साथ 6,900-6,950 रुपये प्रति क्विंटल पर बंद हुआ। दादरी मंडी में बिकने वाला सरसों तेल 225 रुपये की गिरावट के साथ 14,250 रुपये प्रति क्विंटल, सरसों पक्की और कच्ची घानी तेल का भाव क्रमशः 40-40 रुपये की गिरावट के साथ क्रमशः 2,390-2,490 रुपये और 2,390-2,535 रुपये टिन (15 किलो) पर बंद हुआ। सोयाबीन दाने और सोयाबीन लूज के थोक भाव क्रमशः 100-100 रुपये के सुधार के साथ क्रमशः 4,800-4,850 रुपये और 4,500-4,550 रुपये प्रति क्विंटल पर बंद हुए।

दिल्ली में सोयाबीन तेल 125 रुपये के सुधार के साथ 13,550 रुपये प्रति क्विंटल, इंदौर में सोयाबीन तेल 125 रुपये के सुधार के साथ 13,150 रुपये और सोयाबीन डीगम तेल का दाम 135 रुपये के सुधार के साथ 10,325 रुपये प्रति क्विंटल पर बंद हुआ। मूंगफली तेल-तिलहन की कीमतों में स्थिरता देखने को मिली। मूंगफली तिलहन 6,450-6,825 रुपये क्विंटल, मूंगफली तेल गुजरात 15,500 रुपये क्विंटल और मूंगफली साल्वेंट रिफाइंड तेल 2,485-2,785 रुपये प्रति टिन के पूर्व सप्ताहांत के भाव पर स्थिर बने रहे। दूसरी ओर सीपीओ तेल का दाम 175 रुपये के सुधार के साथ 11,375 रुपये प्रति क्विंटल, पामोलीन दिल्ली का भाव 100 रुपये के सुधार के साथ 13,100 रुपये प्रति क्विंटल तथा पामोलीन एक्स कांडला तेल का भाव 100 रुपये के सुधार के साथ 12,100 रुपये प्रति क्विंटल पर बंद हुआ। बिनौला तेल के दाम भी 75 रुपये सुधार के साथ 12,275 रुपये प्रति क्विंटल पर स्थिर बंद हुए।

कोल इंडिया की अनुषंगी कंपनियां 2030 तक शेयर बाजार में सूचीबद्ध होंगी

- लक्ष्य प्रशासन सुधार, पारदर्शिता और परिसंपत्ति मौद्रिकरण के जरिए मूल्य सृजन

नई दिल्ली (ईएमएस)। प्रधानमंत्री कार्यालय (पीएमओ) ने कोयला मंत्रालय को निर्देश दिया है कि सरकारी कंपनी कोल इंडिया लिमिटेड (सीआईएल) की सभी अनुषंगी कंपनियों को 2030 तक शेयर बाजार में सूचीबद्ध किया जाए। इस कदम का उद्देश्य कंपनी के प्रशासन को सुव्यवस्थित करना, पारदर्शिता बढ़ाना और परिसंपत्ति मौद्रिकरण के जरिए मूल्य सृजन करना है। सीआइएल देश के कुल घरेलू कोयला उत्पादन में 80 प्रतिशत से अधिक योगदान देती है। कंपनी अपनी आठ अनुषंगी कंपनियों के माध्यम से काम करती है, जिनमें ईस्टर्न कोलफील्ड्स लिमिटेड, भारत कोकिंग कोल लिमिटेड (बीसीसीएल), सेंट्रल कोलफील्ड्स लिमिटेड, वेस्टर्न कोलफील्ड्स लिमिटेड, साउथ ईस्टर्न कोलफील्ड्स लिमिटेड, नॉर्दर्न कोलफील्ड्स लिमिटेड, महानदी कोलफील्ड्स लिमिटेड और सेंट्रल माइन प्लानिंग एंड डिजाइन इंस्टीट्यूट लिमिटेड शामिल हैं। सूचीबद्ध करने की प्राथमिकता के तहत बीसीसीएल और सीएमपीडीआई को मार्च 2026 तक लिस्टिंग कराने की योजना है।

बीसीसीएल के घरेलू और अंतरराष्ट्रीय रोडशो पूरे हो चुके हैं और प्रक्रिया बिना किसी देरी के पूरी गति से चल रही है। इस योजना से सीआईएल की संचालन क्षमता मजबूत होगी और निवेशकों के लिए नए अवसर पैदा होंगे।

जीएमआर नया ताइफ अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डा परियोजना के लिए पात्र

हैदराबाद ।

सऊदी अरब के नेशनल सेंटर फॉर प्राइवेटाइजेशन एंड पीपीपी (एनसीपी) ने जीएमआर समूह को नया ताइफ अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डा परियोजना के लिए बोली लगाने की पात्रता प्रदान की है। इस परियोजना में बेंगलुरु इंटरनेशनल एयरपोर्ट लिमिटेड टेमासेक, तुर्की की टीएवी एयरपोर्ट्स, मादा इंटरनेशनल होल्डिंग, आयरलैंड की डीएए इंटरनेशनल और काल्योन इंसात गठजोड़ भी पात्र हैं। 80 करोड़ अमेरिकी डॉलर की इस परियोजना को सार्वजनिक निजी साझेदारी (पीपीपी) मॉडल के तहत बीटीओ अनुबंध के आधार पर 30 वर्ष की अवधि के लिए विकसित किया जाएगा। नया हवाई अड्डा आधुनिक वाणिज्यिक यात्री टर्मिनल, सहायक भवन, उपयोगिता नेटवर्क, कार पार्किंग और संपर्क सड़कें प्रदान करेगा। इसका लक्ष्य यात्री क्षमता और मांग के अनुसार उच्च स्तरीय संचालन सुनिश्चित करना है।

स्टीव वॉजनिएक- एप्पल की नींव रखने वाले शांत और उदार इंजीनियर

नई दिल्ली । स्टीव जॉब्स के नाम से एप्पल प्रसिद्ध है, लेकिन इसके असली निर्माता स्टीव वॉजनिएक थे। वे तकनीक को लोगों की जिंदगी आसान बनाने के लिए बनाते थे और दौलत या शोहरत के पीछे नहीं भागे। बचपन में ही वॉजनिएक टीवी और रेडियो खोलकर समझते थे कि ये कैसे काम करते हैं। घर पर खुद कंप्यूटर बनाना उनका शौक बन गया। 975 में एलटेयर 8800 से प्रेरित होकर उन्होंने एप्पल बनाया। स्टीव जॉब्स ने इसकी क्षमता देखी और दोनों ने कैलिफोर्निया के एक छोटे गैराज में मिलकर एप्पल की नींव रखी। वॉजनिएक ने दौलत समेटने के बजाय बच्चों को कोडिंग सिखाना चुना और अपने कई एप्पल शेयर उन कर्मचारियों को दे दिए, जिनके पास कुछ नहीं था। जब उनसे पूछा गया कि उन्होंने इतना सब क्यों दान कर दिया, तो उनका जवाब था, यह सही लगा। मैं चाहता था कि सफलता सबके साथ बांटी जाए। वॉजनिएक दुनिया के सबसे अमीर लोगों में शामिल हो सकते थे, लेकिन उन्होंने सबसे उदार इंसान बनना चुना, जहां स्टीव जॉब्स ने डिजाइन में परफेक्शन खोजा, वहीं स्टीव वॉजनिएक ने उदारता में। आज भी वॉजनिएक दौलत या शोहरत की बात नहीं करते। वे शिक्षा, रचनात्मकता और सादगी की बात करते हैं।

सोना और चांदी में निवेश के लिए ईटीएफ बन रहे पसंदीदा विकल्प: विशेषज्ञ

डिजिटल सोना सुविधाजनक है और कम राशि में निवेश संभव

नई दिल्ली ।

इस साल सोने और चांदी की कीमतों में रिकॉर्ड वृद्धि देखने को मिली है। मल्टीकमोडिटी एक्सचेंज (एमसीएक्स) में सोना 76,772 रुपये प्रति 10 ग्राम से बढ़कर 1,39,890 रुपये हो गया, जबकि चांदी 87,300 रुपये प्रति किलो से 2,40,300 रुपये पर पहुंच गई। इससे निवेशकों में मूल्यवान धातुओं में निवेश का उत्साह बढ़ गया है।` विशेषज्ञों के अनुसार गोल्ड और सिल्वर ईटीएफ (एक्सचेंज ट्रेडेड फंड) निवेशकों के लिए सबसे सुविधाजनक विकल्प हैं। एक बाजार विशेषज्ञ ने बताया कि ईटीएफ में निवेश करने से सोना या चांदी रखने की झंझट नहीं होती और यह उच्च तरलता और कम लेन-देन शुल्क प्रदान करता है। ईटीएफ में कम इकाई मूल्य, रखरखाव की कोई लागत और शुद्धता की गारंटी भी उपलब्ध है। यदि निवेशक प्रत्यक्ष स्वामित्व को महत्व देते हैं, तो सोने और चांदी के सिक्के या बिस्कुट बेहतर विकल्प हैं। हालांकि, इसमें रखरखाव, बीमा लागत और

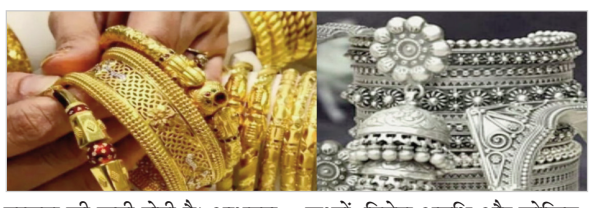

तरलता की कमी होती है। आभूषण निवेश करने योग्य नहीं माना जाता, क्योंकि इसमें बनाने का अतिरिक्त शुल्क लगता है। डिजिटल सोना सुविधाजनक है और कम राशि में निवेश संभव है, लेकिन यह सेबी द्वारा विनियमित नहीं है।

विश्लेषकों का कहना है कि निवेशकों को अपने व्यक्तिगत लक्ष्यों, निवेश अवधि और जोखिम सहनशीलता के आधार पर विकल्प चुनना चाहिए। ईटीएफ, भौतिक धातु, वायदा- विकल्प या डिजिटल सोना–हर विकल्प के अपने फायदे और जोखिम हैं। विविध निवेश अपनाने से सुरक्षा, तरलता और वृद्धि क्षमता में संतुलन बनाए रखने में मदद मिल सकती है।

अदाणी समूह रक्षा क्षेत्र में करेगा 1.8 लाख करोड़ का निवेश

नई दिल्ली ।

अदाणी समूह अगले साल रक्षा विनिर्माण क्षेत्र में 1.8 लाख करोड़ रुपये निवेश करने की योजना बना रहा है। कंपनी का उद्देश्य मानवरहित प्रणालियों, उन्नत हथियारों और एआई आधारित बहु-क्षेत्रीय अभियानों में अपनी क्षमताओं को मजबूत करना है। इसके तहत अदाणी डिफेंस एंड एयरोस्पेस ने 2025 में लंबी योजना प्रक्रियाओं से हटकर त्वरित तैनाती की दिशा में कदम बढ़ाया। कंपनी के कुछ सैन्य उपकरणों का उपयोग ऑपरेशन सिंदूर में भी किया गया। कंपनी का निवेश मुख्य रूप से मानवरहित और स्वायत्त प्रणालियों, उन्नत निर्देशित हथियारों, सेंसर और इलेक्ट्रॉनिक्स, एआई आधारित बहु-क्षेत्रीय संचालन और रखरखाव, मरम्मत और प्रशिक्षण अवसंरचना पर केंद्रित रहेगा। स्वायत्त प्रणालियां हवा, समुद्र और जमीन तीनों क्षेत्रों में काम करती हैं और न्यूनतम मानवीय हस्तक्षेप के साथ संचालित होती हैं। इनसे सैन्य पहुंच बढ़ती है और सैनिकों के लिए जोखिम कम होता है। अदाणी डिफेंस एंड एयरोस्पेस ने 2025 में अपने कुछ उपकरणों को ऑपरेशन सिंदूर में तैनात किया। इसी वर्ष कंपनी के 'दृष्टि 10 यूएवी को लंबी अवधि के निगरानी और टोही मिशनों के लिए भारतीय नौसेना और थल सेना में शामिल किया गया। अदाणी डिफेंस एंड एयरोस्पेस अब भारत की सबसे बड़ी एकीकृत निजी रक्षा कंपनी बन चुकी है। इसकी क्षमताओं में मानवरहित हवाई और जलीय प्रणालियां, प्रतिरोधी यूएएस समाधान, निर्देशित हथियार, छोटे हथियार और गोला-बारूद, विमान रखरखाव, मरम्मत और प्रशिक्षण शामिल हैं।

रॉल्स-रॉयस भारत को बनाएगा तीसरा गृह बाजार, करेगी बड़ा निवेश

जेट इंजन और नौसैनिक प्रणोदन कार्यक्रमों पर नजर

नई दिल्ली ।

ब्रिटेन की एयरो-इंजन और उन्नत इंजीनियरिंग कंपनी रॉल्स-रॉयस भारत में बड़ा निवेश करने पर विचार कर रही है। कंपनी ने कहा है कि भारत को वह ब्रिटेन के बाहर अपना तीसरा ÷गृह बाजार बनाने की योजना बना रही है। रॉल्स-रॉयस पहले ही अमेरिका और जर्मनी को अपने प्रमुख अंतरराष्ट्रीय बाजार के रूप में विकसित कर चुकी है। कंपनी की प्राथमिकता नई पीढ़ी के जेट इंजन को भारत में विकसित करना है, ताकि एएमसीए (उन्नत मध्यम युद्धक विमान) कार्यक्रम के तहत भारत में बनने वाले लड़ाकू विमानों को शक्ति दी जा सके। कंपनी भारतीय नौसेना की युद्धक क्षमता बढ़ाने में भी महत्वपूर्ण भूमिका निभा सकती है। रॉल्स-रॉयस इलेक्ट्रिक प्रणोदन की जरूरतों को पूरा करने में मदद करेगी और नौसैनिक प्रणोदन के लिए भारत में इंजन निर्माण की दिशा में योगदान देगी। कंपनी भारत में अपने प्रभावी निवेश पर नजर रखे हुए है। रॉल्स-रॉयस की योजना दो रक्षा पीएसयू के साथ दो समझौता ज्ञापनों को अंतिम रूप देने की है। इनमें पहला अर्जुन टैंक के लिए इंजन निर्माण से जुड़ा होगा, जबकि दूसरा भविष्य के युद्धक वाहनों के लिए इंजन उत्पादन से संबंधित है। रॉल्स-रॉयस अब केवल रक्षा तक सीमित नहीं रहेगी, बल्कि नौसैनिक प्रणोदन, थल प्रणालियों, विनिर्माण, उन्नत इंजीनियरिंग कौशल और प्रौद्योगिकी विकास तक अपने विस्तार की योजना बना रही है।

रॉल्स-रॉयस के अनुसार भारत में निवेश का अवसर इसलिए भी है क्योंकि देश के पास बड़ा पैमाना, स्पष्ट नीति और मजबूत रक्षा तथा औद्योगिक पारिस्थितिकी तंत्र है। कंपनी का उद्देश्य भारत को वैश्विक स्तर पर अपने रणनीतिक बाजारों में शामिल करना है।

वॉरेन बफे की जिद ने बदल दिया निवेश की दुनिया का इतिहास

- एक कमजोर टेक्सटाइल से ताकतवर होल्डिंग कंपनी बनने तक का सफर

नई दिल्ली ।

सिर्फ 12 सेंट की रकम से शुरू हुई एक जिद ने निवेश की दुनिया का इतिहास बदल दिया। यह कहानी है दुनिया के दिग्गज निवेशक वॉरेन बफे और उनकी कंपनी बर्कशायर हैथवे की, जिसकी आज वैल्यूएशन 900 अरब डॉलर से भी ज्यादा है। साल 1964 में बर्कशायर हैथवे एक घाटे में चल रही टेक्सटाइल कंपनी थी। कपड़ा, ऊन और कॉटन का कारोबार करने वाली इस कंपनी के शेयर बेहद सस्ते थे। वॉरेन बफे ने इसमें मौका देखा और धीरे-धीरे शेयर खरीदकर करीब 7 फीसदी हिस्सेदारी हासिल कर ली। इसी दौरान कंपनी के सीईओ ने बफे को 11.50 डॉलर प्रति शेयर पर हिस्सेदारी वापस खरीदने का ऑफर दिया। बफे ने इस प्रस्ताव को स्वीकार कर लिया, लेकिन जब कागजी प्रक्रिया पूरी हुई तो सीईओ ने कीमत 12.5 सेंट कम कर दी।

यही छोटा सा फर्क बफे के लिए अपमान बन गया। उन्होंने शेयर बेचने के बजाय और अधिक शेयर खरीदने का फैसला किया। एक साल से भी कम समय में उनकी हिस्सेदारी 43 फीसदी तक पहुंच गई और कंपनी पर उनका नियंत्रण हो गया। बफे ने सबसे पहले सीईओ को बाहर का रास्ता दिखाया। बाद में उन्होंने इस फैसले को अपनी सबसे बड़ी गलती भी माना। हालांकि, उन्होंने बर्कशायर हैथवे को एक होल्डिंग कंपनी के रूप में इस्तेमाल किया और इसके जरिए बीमा, बैंकिंग, रेलवे और बड़ी कंपनियों में निवेश शुरू किया। 1985 में टेक्सटाइल बिजनेस बंद हुआ और यहीं से असली बर्कशायर हैथवे की कहानी शुरू हुई, जो आज निवेश की दुनिया की सबसे बड़ी मिसाल बन चुकी है।

Web site : www.krantisamay.com & epaper.krantisamay.com www.facebook.com/krantisamay1 www.twitter.com/krantisamay1

केन्द्रीय अनुबंध में शुभमन को मिल सकता है प्रमोशन, विराट और रोहित का होगा डिमोशन

मुम्बई (एजेंसी)। भारतीय क्रिकेट बोर्ड (बीसीसीआई) साल 2026 के लिए केन्द्रीय अनुबंध में बदलाव कर सकता है। आने वाले दिनों मे इस बार में घोषणा होने की संभावना है। एक रिपोर्ट के अनसार बीसीसीआई खिलाड़ियों की ग्रेडिंग में बड़े बदलाव करने जा रहा है। इसके तहत जहां अनुभवी बल्लेबाजों रोहित शर्मा और विराट कोहली का डिमोशन हो सकता है। वहीं शुभमन गिल का प्रमोशन हो सकता है।

रोहित और विराट अभी तक ए प्लस ग्रेड में रखा गया था पर अब उन्हें इसे हटना पड़ेगा क्योंकि अब ये दोनो एक ही प्रारुप खेलते हैं। ए प्लस केवल उन्हीं को मिलता है जो तीनो ही प्रारुप खेलते हैं। रोहित और विराट ने टेस्ट और टी20 से संन्यास ले लिया है। वहीं शुभमन गिल अब दो प्रारुप में कसानी कर रहे हैं। इसलिए उन्हें ए प्लस ग्रेड में लाया जाना तय है। शुभमन का प्रदर्शन भी लगातार अच्छा रहा है। वहीं युवा विकेटकीपर बल्लेबाज ईशान किशन को भी इस बार अनुबंध मिल सकता है।

ईशान साल 2025 की केन्द्रय अनुबंध सूची में शामिल नहीं थे पर अब उन्हें 2026 की नई सूची में शामिल किया जा सकता है। ईशान को टी20 विश्व कप 2026 के लिए भारतीय टीम में शामिल किया गया है, इससे भी उन्हें अनुबंध में जगह मिलना तय माना जा रहा है।

ग्रेड में शुभमन के अलावा रवींद्र जडेजा और जसप्रीत बुमराह को ए प्लस + ग्रेड में रखा जा सकता है। ये तीनों खिलाड़ी सभी प्रारुपों में भारतीय टीम से खेल रहे हैं। खिलाड़ियों के केन्द्रीय अनुबंध के अलावा बीसीसीआई घरेलू क्रिकेट में अंपायरों और मैच रेफरी की मैच फीस बढ़ाने की भी घोषणा कर सकता है। यह फैसला घरेलू सर्किट के लिए अहम माना जा रहा है।

भारतीय टीम का प्रतिनिधित्व करने के लिए पाकिस्तान खिलाड़ी पर बड़ी कार्रवाई, मिली कठोर सजा

कराची (एजेंसी)। पाकिस्तान के जाने-माने इंटरनेशनल कबड्डी खिलाड़ी उबैदुल्लाह राजपूत को नेशनल फेडरेशन ने कठोर सजा देते हुए हुए उन्हें अनिश्चित काल के लिए बैन कर दिया है क्योंकि उन्होंने इस महीने की शुरुआत में बहरीन में एक प्राइवेट टूर्नामेंट में भारतीय टीम के लिए खेला था। पाकिस्तान कबड्डी फेडरेशन (PKF) ने एक इमरजेंसी मीटिंग के बाद यह बैन लगाया। फेडरेशन ने राजपूत को बिना फेडरेशन या दूसरे संबंधित अधिकारियों से जरूरी नो-ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट (NOC) लिए विदेश जाकर टूर्नामेंट खेलने का दोषी पाया।

PKF के सेक्रेटरी राणा सरवर ने कहा कि राजपूत के पास डिसिप्लिनरी कमेटी के सामने अपील करने का अधिकार है। सरवर ने कहा कि फेडरेशन ने इस बात को गंभीरता से लिया कि राजपूत न सिर्फ बिना NOC के विदेश गए बल्कि उन्होंने भारत टीम का प्रतिनिधित्व किया, उसकी जर्सी पहनी और एक मैच जीतने के बाद भारतीय झंडा अपने कंधों पर लपेट लिया। सरवर ने कहा, 'लेकिन उसने (राजपूत) दावा किया है कि यह पूरी तरह से गलतफहमी थी और उसे कभी नहीं बताया गया था कि वह जिस टीम के लिए प्राइवेट टूर्नामेंट में खेलेगा, वह भारतीय टीम होगी। लेकिन वह फिर भी NOC नियमों का उल्लंघन करने का दोषी है।' राजपूत तब मुश्किल में पड़ गए जब GCC कप के दौरान भारतीय जर्सी पहने और भारतीय झंडा लहराते हुए उनके वीडियो और तस्वीरें सोशल मीडिया पर वायरल हो गईं। सरवर ने आगे कहा कि NOC लिए बिना इस इवेंट में हिस्सा लेने के लिए दूसरे खिलाड़ियों पर भी बैन लगाया गया है और जुर्माना लगाया गया है। राजपूत ने पहले माफी मांगी थी, जिसमें कहा था कि उन्हें बहरीन में टूर्नामेंट में खेलने के लिए बुलाया गया था और उन्हें एक प्राइवेट टीम में शामिल किया गया था।

उन्होंने कहा था, 'मुझे बाद में पता चला कि उन्होंने टीम का नाम भारत टीम रखा था और मैंने आयोजकों से कहा कि वे भारत और पाकिस्तान के नामों का इस्तेमाल न करें। पहले भी प्राइवेट कॉम्पिटिशन में, भारतीय और पाकिस्तानी खिलाड़ी एक साथ एक प्राइवेट टीम के लिए खेले हैं, लेकिन कभी भी भारत या पाकिस्तान के नाम से नहीं। मुझे बाद में पता चला कि मुझे गलत तरीके से भारतीय टीम के लिए खेलते हुए दिखाया गया, जिसके बारे में मैं विवाद के बाद सोच भी नहीं सकता।'

अब 2026 टी20 विश्वकप जीतना चाहती है भारतीय महिला टीम : हरमनप्रीत

-श्रीलंकाई टीम के खिलाफ सीरीज से अभ्यास का अच्छा अवसर मिला

त्रिवेंद्रम (एजेंसी)। भारतीय महिला क्रिकेट टीम की कप्तान हरमनप्रीत कौर ने कहा है कि अब उनकी टीम का लक्ष्य 2026 टी20 विश्वकप जीतना है। भारतीय टीम ने इसी साल हरमनप्रीत की कप्तान में एकदिवसीय विश्वकप जीता था जिसके बाद से ही उसके हौंसले बुलंद हैं। श्रीलंका के खिलाफ जारी सीरी में भी टीम का प्रदर्शन अच्छा रहा है और उसने पांच मैचों की सीरीज के शुरुआती तीन मैच आसानी से जीत लिए हैं।

हरमनप्रीत ने साफ किया कि श्रीलंका के खिलाफ इस सीरीज से आने वाले टी20 विश्वकप के लिए टीम को अभ्यास का अवसर मिला है। उन्होंने कहा कि टीम ने श्रीलंका के खिलाफ अधिक आक्रामक रवैया अपनाया है। ताकि एक प्रयोग किया जा सके। हरमनप्रीत ने कहा, एकदिवसीय विश्वकप जीतने के बाद हमने तय किया था कि टी20 क्रिकेट में अपने स्तर को और आगे ले जाना है। इसी कारण आक्रामक रुख अपनाया गया है। विश्व कप में जीत के लिए आक्रामक तरीके से खेलना बहुत जरूरी होता है। इसी को देखते हुए अभ्यास के तौर पर इस सीरीज में टीम आक्रामक रही।

हरमनप्रीत ने कहा कि भारतीय गेंदबाजों ने श्रीलंका के खिलाफ अच्छा प्रदर्शन किया है। साथ ही कहा कि इससे भारतीय टीम की गेंदबाजी ताकत उभरकर सामने आयी है। टी20 प्रारुप में गेंदबाजों की भूमिका बेहद अहम होती है। इसमें विरोधी टीम को छोटे स्कोर पर रोकना होता है जिसमें भारतीय गेंदबाज सफल रहे हैं।

चमारी अथापथु ने रचा इतिहास, ऐसा करने वाली पहली श्रीलंकाई महिला क्रिकेटर बनीं

तिरुवनंतपुरम (केरल) (एजेंसी)। श्रीलंका की महिला कप्तान चमारी अथापथु ने इतिहास रच दिया है। वह अपने देश के लिए 150 टी20आई मैच खेलने वाली पहली खिलाड़ी बन गई हैं। इस अनुभवी क्रिकेटर ने रविवार को तिरुवनंतपुरम में हरमनप्रीत कौर की अगुवाई वाली भारतीय महिला टीम के खिलाफ 5 मैचों की सीरीज के चौथे टी20आई के दौरान यह ऐतिहासिक उपलब्धि हासिल की।

महिला टी20आई क्रिकेट में अथापथु ने 25.23 की औसत और 109.97 के स्ट्राइक रेट से 3507 रन बनाए हैं जिसमें तीन शतक और 13 अर्धशतक शामिल हैं। गेंदबाजी में 35 वर्षीय खिलाड़ी ने 25.73 की औसत और 6.62 की इकॉनमी से 63 विकेट लिए हैं। उनके नाम एक बार 4 विकेट लेने का रिकॉर्ड है। इससे पहले श्रीलंका ने टॉस जीतकर ग्रीनफील्ड इंटरनेशनल स्टेडियम में भारत के खिलाफ चौथे टी20आई में पहले गेंदबाजी करने का फैसला किया।

भारतीय महिला और श्रीलंकाई महिला टीमें टी20आई क्रिकेट में 29 बार एक-दूसरे का सामना कर चुकी हैं। इनमें से ब्लू टीम ने 23 जीत हासिल की हैं और 5 हार का सामना किया है। दोनों देशों के बीच एक मैच का कोई नतीजा नहीं निकला। चल रही पांच मैचों की टी20आई सीरीज में भारत ने पहला मैच 8 विकेट से, दूसरा 7 विकेट से और तीसरा 8 विकेट से जीतकर 3-0 की अजेय बढ़त बना ली है। मेहमान टीम चौथे टी20आई में वापसी करने की कोशिश करेगी।

टॉस जीतने के बाद अथापथु ने कहा, 'ओस के कारण पीछा करना थोड़ा आसान है। हमें अपना सर्वश्रेष्ठ क्रिकेट खेलना होगा और कम से कम 140 रन बनाने की कोशिश करनी होगी। यह एक अच्छा स्कोर होगा। हमारी टीम में दो बदलाव हैं, मल्की मदारा और इनोका राणावीरा आज आराम कर रही हैं, काव्या कविंदी और रश्मिका टीम में हैं।''

भारतीय कप्तान हरमनप्रीत कौर ने कहा, 'हम आज पहले बल्लेबाजी करना चाह रहे थे, हम खुश हैं। जेमीमा नहीं खेल रही हैं क्योंकि वह ठीक नहीं हैं और क्रांति आराम कर रही हैं। अरुंधति और हरलीन वापस आ गई हैं। यह हर किसी को मौका देने के लिए एक आदर्श श्रृंखला है। खुशी है कि यह सब योजना के तहत आ रहा है। मैं कोई लक्ष्य दिमाग में नहीं रख रही हूं। उम्मीद है कि हम अच्छा स्कोर बनाएंगे।'

लेइंग इलेवन

भारत महिला : शैफाली वर्मा, स्मृति मंधाना, हरलीन देयोल, हरमनप्रीत कौर (कप्तान), ऋचा घोष (विकेटकीपर), दीप्ति शर्मा, अमनजोत कौर, अरुंधति रेड्डी, वैष्णवी शर्मा, रेणुका सिंह ठाकुर, श्री चरणी।

श्रीलंका महिला : हासिनी परेरा, चमारी अथापथु (कप्तान), हर्षिता समरविक्रमा, कविशा दिलहारी, इमेशा दुलानी, नीलाक्षिका सिल्वा, कौशानी नुथ्यांगना (विकेटकीपर), मालशा शेहानी, रश्मिका सेवंडी, काव्या कविंदी, निमशा मदुशानी।

ब्रेट ली ऑस्ट्रेलियाई क्रिकेट के हॉल ऑफ फेम में शामिल

सिडनी । ऑस्ट्रेलिया के पूर्व तेज गेंदबाज ब्रेट ली को संन्यास के एक दशक से भी अधिक समय के बाद हॉल ऑफ फेम में जगह मिली है। क्रिकेट ऑस्ट्रेलिया (सीए) के अनुसार ब्रेट ली को साल 1999 से 2012 तक शानदार प्रदर्शन के कारण सम्मानित किया जा रहा है। इस तेज गेंदबाज ने अपने करियर के 76 टेस्ट मैचों में 310 विकेट लेने के साथ ही 221 एकदिवसीय मैच मैचों में 380 विकेट लिए। इसके अलावा 25 टी20 अंतरराष्ट्रीय मैचों में 28 विकेट अपने नाम किये। इस गेंदबाज ने बिग बैश लीग (बीबीएल) में सिक्सर्स की ओर से भी काफी अच्छा प्रदर्शन किया है। ली एशेज विजेता टीम का हिस्सा रहे हैं। इसके अलावा उनके रहते टीम ने तीन विश्वकप कप खिताब भी जीते हैं। वह साल 1999, 2003 और 2007 की खिताब विजेता टीम में शामिल रहे हैं। ली ने साल 2008 में एलन बॉर्डर पदक जीता और साल 2006 में उन्हें विजडन क्रिकेटर ऑफ द ईयर का सम्मान दिया गया। वह ऑस्ट्रेलिया के सबसे बेहतरीन खिलाड़ियों में से एक रहे हैं। इस तेज गेंदबाज के प्रशंसकों की भारी तादाद है। ऑस्ट्रेलियाई क्रिकेट हॉल ऑफ फेम के चेयरमैन पीटर किंग ने कहा, 'ब्रेट ली ऑस्ट्रेलियाई क्रिकेट हॉल ऑफ फेम में शामिल होने के योग्य हैं। वह विश्व के सबसे तेज गेंदबाजों में से एक होने के साथ ही ऑस्ट्रेलियाई क्रिकेट के ब्रांड एंबेसडर भी रहे हैं।' संन्यास के बाद से ही वह एक कमेंटेटर के रूप में खेल से जुड़े हुए हैं। ऑस्ट्रेलियाई क्रिकेट हॉल ऑफ फेम उन खिलाड़ियों का सम्मान करता है जिनके करियर ने खेल पर अपना प्रभाव छोड़ा है।'

स्टार्क डब्ल्यूटीसी सत्र में सबसे अधिक विकेट लेने वाले गेंदबाज बने

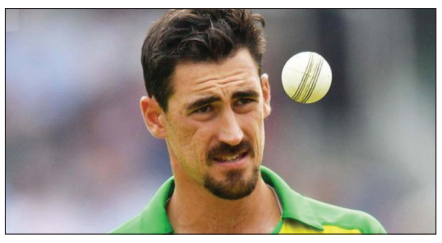

मेलबर्न। ऑस्ट्रेलिया के अनुभवी तेज गेंदबाज मिचेल स्टार्क ने इंग्लैंड के खिलाफ बॉक्सिंग डे टेस्ट में दो विकेट लेने के साथ ही एक अहम उपलब्धि अपने नाम की है। अब स्टार्क इस साल विश्व टेस्ट चैंपियनशिप (डब्ल्यूटीसी) 2025-27 सत्र में सबसे अधिक विकेट लेने वाले गेंदबाज बन गये हैं। अभी तक इस साल डब्ल्यूटीसी में सबसे अधिक विकेट भारत के में तेज गेंदबाज मोहम्मद सिराज के नाम पर थे। वहीं अब सिराज दूसरे नंबर पर खिसक गये हैं। स्टार्क पेसर स्टार्क ने डब्लयूटीसी 2025-27 में अब तक 7 मैचों की 14 पारियों में 41 विकेट लिए हैं। वहीं सिराज ने 9 टेस्ट मैचों में 39 विकेट अपने नाम किये हैं। स्टार्क ने अब तक इस एशेज 2025-26 सीरीज में सबसे अधिक विकेट लिए हैं। इंग्लैंड के खिलाफ चार टेस्ट मैचों में उन्होंने 26 विकेट लिए हैं। स्टार्क ने अब तक 53 टेस्ट मैचों में 217 विकेट अपने नाम किए हैं। अगर वह एशेज सीरीज के पांचवें टेस्ट में 8 विकेट और हासिल कर लेते हैं, तो वह अपने ही साथी गेंदबाज नाथन लायन को पीछे छोड़कर डब्ल्यूटीसी इतिहास के सबसे ज्यादा विकेट लेने वाले गेंदबाज बन सकते हैं। डब्ल्यूटीसी में सबसे अधिक विकेट लेने वाले गेंदबाजों में तीसरे नंबर पर इंग्लैंड के जोश टंग हैं। टंग ने 5 मैच में 31 विकेट लिए हैं। वहीं दक्षिण अफ्रीका के साइमन हार्मर ने 4 मैच में 30 और इंग्लैंड के बेन स्टोक्स ने 8 मैच में 30 विकेट लिए हैं।

अभिषेक शर्मा ने नेट अभ्यास के दौरान दिखाया जलवा, गेंद को मैदान से भेजा बाहर

जयपुर (एजेंसी)। पंजाब के कप्तान अभिषेक शर्मा यहां रविवार की सुबह अपने नेट सत्र के लगभग 10 मिनट बाद रुके और टीम के अपने साथी खिलाड़ी गौरव चौधरी की ओर मुड़े और एक सवाल पूछा जिससे उनके इरादे और कल्पना का पता चलता है। उन्होंने पूछा, 'क्षेत्ररक्षण कैसा है।'

अभिषेक ने यह सवाल काल्पनिक क्षेत्ररक्षकों के बारे में पूछा। ऑफ स्पिनर चौधरी ने तुरंत जवाब दिया, 'मिड ऑफ पर एक रन बचाने के लिए रखा है।' इसके बाद जो हुआ वह अनुमानित लेकिन रोमांचक था। अभिषेक ने अपने चिरपरिचित अंदाज में बल्ला घुमाया और गेंद को मैदान से बाहर भेज दिया। दुनिया के नंबर एक टी20 बल्लेबाज ने लगभग एक घंटे अभ्यास किया और इस दौरान डिफेंस को कोई तवज्जो नहीं दी। उन्होंने जयपुर शहर की सीमा से थोड़ी दूर खेत की जमीन पर बने खूबसूरत अनंतम क्रिकेट ग्राउंड पर कम से कम 45 छक्के लगाए।

यह एक विशेष बल्लेबाजी सत्र जैसा लग रहा था जहां अभिषेक सिर्फ स्पिनरों का सामना करना चाहते थे। एक ऐसी पिच पर ऑफ स्पिनर, लेग स्पिन और बाएं हाथ की धीमी गेंदबाजी का सामना जहां गेंद बार-बार रुककर आ रही थी और अगर गेंदबाज सही जगह पर गेंद डालते तो काफी टर्न मिल रहा था। बाएं हाथ के इस बल्लेबाज ने मैदानकर्मियों को हल्का रोलर चलाने के लिए कहा लेकिन मुश्किलें कम नहीं हुई क्योंकि नेट गेंदबाजों की गेंदें लगातार परेशान कर रही थीं। कुछ गेंद अप्रत्याशित रूप से ऊपर उठ रही थीं जबकि कुछ खतरनाक तरीके से नीचे रह रहीं थी।

जब भी लेंथ थोड़ी छोटी होती तो अभिषेक को परेशानी होती लेकिन जिस तरह से वह अपने पैरों का इस्तेमाल कर रहे थे वह देखना बहुत शानदार था। गेंद को खेलने से चूकने और उछलते हुए देखने के बाद वह पिच पर आगे बढ़ते और अपने बल्ले से निशान पर टैप करते और फिर अपनी महारत दिखाते। छोटी लेंथ की गेंद पर वह पिच पर आगे बढ़कर ऑफ स्पिन और गुगली (जो बाएं हाथ के बल्लेबाज से दूर जाती थी) के खिलाफ एक्स्ट्रा कवर के ऊपर से इनसाइड-आउट शॉट लगाते थे। कम से कम पांच बार गेंद पास की एक ऊंची रिहायशी इमारत के परिसर में गिरी।

इनसाइड-आउट शॉट इतनी बार दोहराया गया कि टीम के मुख्य कोच संदीप शर्मा ने मजाक में कहा, 'तू अपना शतक पूरा करने के लिए सिर्फ एक्स्ट्रा कवर के ऊपर ही छक्के मारना चाहता है।% गलत शॉट के लिए शॉर्ट एक्स्ट्रा कवर पर एक लाल क्षेत्ररक्षण नेट लगाया गया था। वह एक बार उस जाल में फंस गए लेकिन जल्दी ही सामंजस्य बैठाया और कुछ सीधे छक्के मारने का फैसला किया। जब 25 साल का खिलाड़ी बाकी टीम के लगभग 45 मिनट बाद ट्रेनिंग के लिए आया तो वह पांच केंद्रीय पिच में से एक पर अभ्यास करना चाहते थे। ये सभी लाल मिट्टी की पिचें थीं।

हालांकि मैच की पिच तय नहीं हुई थी इसलिए भारतीय क्रिकेट बोर्ड (BCCI) के नियमों के अनुसार उन्हें वहां बल्लेबाजी करने की इजाजत नहीं थी। फिर उन्होंने लगभग 40 मिनट तक बाएं हाथ की स्पिन गेंदबाजी की और मुख्य कोच तथा सहायक कोच उदय कौल के साथ बल्लेबाजी के बारे में बात की। जब पूरी टीम का सत्र पूरा हो गया तो कप्तान के लिए पैड पहनने का समय था।

उन्होंने शुरू में तेज गेंदबाजों का सामना करने का फैसला किया लेकिन एक युवा नेट गेंदबाज लगातार पांचवें स्टंप की लाइन पर गेंदबाजी कर रहा था जिससे अभिषेक ने सलाह दी, 'भाई, तुम स्टंप्स के करीब गेंदबाजी करो।'' दुनिया के सबसे बेहतरीन टी20 बल्लेबाजों में से एक अभिषेक ने खुद को हर कीमत पर आक्रमक करने के लिए तैयार किया है जो टीम की सामूहिक सोच को दिखाता है। छक्के मारना उनके लिए स्वाभाविक लगता है। एक घंटे के नेट सत्र के दौरान वह तीन से चार बार आउट हुए और हर बार डिफेंस करते हुए। आक्रामक रवैया दिखाते हुए वह हमेशा नियंत्रण में दिखे। कुछ ऐसा ही भारत अगले नौ हफ्तों में देखने की उम्मीद करेगा।

पूर्व इंग्लैंड स्ट्राइकर कैरोल गिरफ्तारी के बाद कोर्ट में पेश होंगे

लंदन । न्यूकैसल यूनाइटेड, लिवरपूल और इंग्लैंड के पूर्व स्ट्राइकर एंडी कैरोल को मंगलवार को कोर्ट में पेश होना है, उन पर नॉन-मोलस्टेशन ऑर्डर का उल्लंघन करने का आरोप है। स्पोर्ट के अनुसार 36 साल के कैरोल, जो अब नेशनल लीग साउथ साइड डेगनहम एंड रेडब्रिज के लिए खेलते हैं, को अप्रैल में गिरफ्तार किया गया था और कथित अपराध एक महीने पहले किया गया था। 36 साल के खिलाड़ी, जिन्होंने इंग्लैंड के लिए 9 मैच खेले हैं और जिन्हें 2011 में लिवरपूल ने उस समय के क्लब रिकॉर्ड फीस 35 मिलियन यूरो में साइन किया था, उन्हें चेम्सफोर्ड मजिस्ट्रेट कोर्ट में पेश होना है। एसेक्स पुलिस ने कहा, 'एक व्यक्ति पर नॉन-मोलस्टेशन ऑर्डर का उल्लंघन करने का आरोप लगाया गया है। एपिंग के रहने वाले 36 साल के एंड्रयू कैरोल को 27 अप्रैल को गिरफ्तार किया गया था और कथित अपराध मार्च की एक घटना से संबंधित हैं। उन्हें 30 दिसंबर को चेम्सफोर्ड मजिस्ट्रेट कोर्ट में पेश होना है।' नॉन-मोलस्टेशन ऑर्डर एक कोर्ट का आदेश होता है जो आमतौर पर किसी व्यक्ति को दूसरे व्यक्ति से बात करने से रोकने के लिए जारी किया जाता है और यह किसी को किसी खास पते या काम की जगह से एक निश्चित दूरी के अंदर आने से भी रोक सकता है। नॉन-मोलस्टेशन ऑर्डर के उल्लंघन की सजा जुर्माने से लेकर सबसे गंभीर मामलों में पांच साल तक की जेल हो सकती है।

भारतीय जूनियर पुरुष हॉकी टीम ने दो बड़े अंतरराष्ट्रीय पदक जीतकर किया वर्ष 2025 का सफल समापन

नई दिल्ली (एजेंसी)। भारतीय जूनियर पुरुष हॉकी टीम ने दो बड़े अंतरराष्ट्रीय पदक सुल्तान ऑफ जोहोर कप में रजत और एफआईएच हॉकी पुरुष जूनियर विश्व कप तमिलनाडु में कांस्य जीतकर वर्ष 2025 का समापन एक बहुत ही सफल साल के तौर पर किया। पूरे साल पीआर श्रीजेश के मार्गदर्शन में कई गहन राष्ट्रीय प्रशिक्षण शिविरों के माध्यम से कोच ने एक टीम बनाई और खिलाड़ियों को दिसंबर में जूनियर विश्व कप के लिए सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन करने के लिए तैयार किया।

भारत की प्रतिस्पर्धी तैयारी जून में चार देशों के टूर्नामेंट से शुरू हुई, जो अच्छी यूरोपीय टीमों के खिलाफ एक महत्वपूर्ण तैयारी का अवसर था। मेजबान जर्मनी के साथ-साथ स्पेन और ऑस्ट्रेलिया का सामना करते हुए, भारतीय जूनियर टीम ने बड़ी टीमों के खिलाफ अपनी योजना परीक्षण किया और टूर्नामेंट में तीसरे स्थान पर रही।

उन्होंने अक्टूबर में 2025 सुल्तान ऑफ जोहोर कप में उसी लय और सीख को आगे बढ़ाया, जहां भारत ने रजत पदक जीतने के लिए एक मजबूत और लगातार प्रदर्शन किया। टीम ने ग्रेट ब्रिटेन, न्यूजीलैंड और मलेशिया पर महत्वपूर्ण जीत दर्ज की और पाकिस्तान के साथ 3-3 से ड्रॉ भी खेला और लीग चरण में शानदार प्रदर्शन के बाद फाइनल में पहुंची।

खिताबी मुकाबले में भारत ने 59वें मिनट में एक दुर्भाग्यपूर्ण गोल खाया और ऑस्ट्रेलिया से 1-2 से हार गई और रजत पदक से संतोष करना पड़ा। यह सारी तैयारी टीम को FIH हॉकी पुरुष जूनियर विश्व कप तमिलनाडु 2025 तक ले गई, जो सीजन का सबसे महत्वपूर्ण टूर्नामेंट था, जहाँ भारत ने घरेलू धरती पर एक यादगार अभियान चलाया।

भारत ने पूल चरण में क्रमशः चिली, ओमान और स्विट्जरलैंड पर तीन आसान जीत के साथ अपने अभियान की शुरुआत की और नॉकआउट राउंड में प्रवेश किया। क्वार्टर-फ़ाइनल एक निर्णायक पल साबित हुआ, क्योंकि भारतीय टीम ने अपना संयम बनाए रखा और शूटआउट में बेल्जियम को 4-3 से हराकर सेमी- फाइनल में जगह बनाई। गोलकीपर प्रिंस दीप सिंह ने शूटआउट में दो अहम बचाव करके शानदार क्लास और हिम्मत दिखाई, जिससे भारत टूर्नामेंट में आगे बढ़ सका।

दुर्भाग्य से भारत सेमी-फाइनल में चैंपियन जर्मनी से 1-5 से हार गया, लेकिन तीसरे/चौथे स्थान के प्लेऑफ में टीम ने शानदार वापसी करते हुए अर्जेंटीना के खिलाफ अविश्वसनीय प्रदर्शन किया और कांस्य पदक हासिल किया। चौथे क्वार्टर तक दो गोल से पीछे होने के बावजूद, भारत ने मैच के आखिरी 15 मिनट में अपना सब कुछ लगा दिया और लगातार चार गोल करके मैच को अपने नाम किया और साल का दूसरा अंतरराष्ट्रीय पदक जीता।

मनमीत सिंह छह गोल के साथ भारत के सबसे अधिक गोल करने वाले खिलाड़ी रहे, जबकि शरदानंद तिवारी और दिलराज सिंह ने पांच-पांच गोल किए। जैसे-जैसे साल आगे बढ़ा, भारतीय जूनियर पुरुष हॉकी टीम एक स्थिर और आत्मविश्वासी टीम के रूप में सामने आई। कई खिलाड़ियों ने अहम पलों पर शानदार प्रदर्शन किया।

कप्तान रोहित पूरे सीजन में एक प्रभावशाली कप्तान के रूप में उभरे और साथ ही उन्होंने अपनी ड्रैगफ्लिकिंग स्किल्स को भी बेहतर बनाया, जो अहम मैचों में एक मुख्य हथियार बन गया। आक्रमण में, दिलराज सिंह और अर्शदीप सिंह ने लगातार गोल किए, जिससे भारत को फॉरवर्ड लाइन में बढ़त मिली। डिफेंस में, प्रिंस दीप सिंह एक भरोसेमंद खिलाड़ी के रूप में परिपक्व हुए, उन्होंने ज़्यादा दबाव वाली स्थितियों में भी शांत प्रदर्शन किया, जबकि अनमोल एक्का टीम के इंजन के रूप में उभरे, उन्होंने मिडफील्ड से खेल को नियंत्रित किया और डिफेंस को आक्रमण से जोड़ा।

FIH हॉकी पुरुष जूनियर विश्व कप तमिलनाडु 2025 में कांस्य पदक और 2025 सुल्तान ऑफा जोहोर कप में रजत पदक के साथ, इस सीजन में न केवल नतीजे मिले, बल्कि हॉकी इंडिया के विजन के तहत भारतीय हॉकी के भविष्य के लिए एक मजबूत नींव भी रखी गई है।

स्पोर्टिफाइड 1.0 में विभिन्न खेलों का शानदार आयोजन

सूरत,अग्रवाल विकास ट्रस्ट युवा शाखा द्वारा आयोजित स्पोर्टिफाइड 1.0 के दूसरे सप्ताह में अनेकों खेलों का आयोजन किया गया। आयोजन में शनिवार को अलथान स्थित क्रेव्स टर्फ में वॉलीबॉल प्रतियोगिता एवं फुटबॉल प्रतियोगिता का आयोजन किया गया। रविवार को महाराजा अग्रसेन पैलेस, वृंदावन हॉल में शतरंज एवं कैरम प्रतियोगिताओं का आयोजन किया गया। सभी खेलों में विजेताओं को ट्रस्ट द्वारा पुरस्कार देकर सम्मानित किया गया। इस मौके पर ट्रस्ट के संजय सरावगी, अनिल अग्रवाल, प्रमोद कंसल, मनोज डोकावाला, शशि भूषण जैन, राहुल अग्रवाल, मनीष अग्रवाल, अंकित झुनझुनवाला सहित अनेकों सदस्य उपस्थित रहे।

संक्षिप्त समाचार

उत्तर-पश्चिमी पाकिस्तान में पुलिस के साथ झड़प में 6 आतंकवादी मारे गए

इस्लामाबाद, एजेंसी। पाकिस्तान के अशांत खैबर पख्तूनख्वा प्रांत में शुक्रवार को पुलिस के साथ हुई मुठभेड़ में कम से कम छह आतंकवादी मारे गए और कई अन्य घायल हो गए। लक्की मारवत जिले में आतंकवादियों द्वारा स्नाइपर राइफलों और क्वाडकॉप्टर हमलों से पुलिस पर हमला करने के बाद गोलीबारी शुरू हो गई। बन्नू के क्षेत्रीय पुलिस कार्यालय के एक बयान में कहा गया है कि आतंकवादियों ने 'क्वाडकॉप्टर हमलों के जरिए ग्रामीणों के घरों को भी निशाना बनाया', जिसके परिणामस्वरूप 'नागरिक हताहत' हुए। इसमें कहा गया है कि आतंकवाद विरोधी विभाग के कमांडो और हथियारबंद स्थानीय लोगों ने गोलीबारी में पुलिस की सहायता की। पुलिस के बयान में कहा गया है, 'स्नाइपर राइफलों और क्वाडकॉप्टरों से लैस आतंकवादियों ने बन्नू जिले की सीमा से लगे ग्रामीण इलाके में पुलिस पर हमला किया, जो सेराई नौरंग कस्बे के शहीद असमतुल्लाह खान खट्टक पुलिस स्टेशन की सीमा के भीतर स्थित है।' इसमें कहा गया है, 'इस हमले के परिणामस्वरूप भीषण गोलीबारी हुई और कानून प्रवर्तकों ने प्रभावी ढंग से जवाबी गोलीबारी की।' हालांकि आधिकारिक प्रेस विज्ञप्ति में पुलिसकर्मियों के हताहत होने के बारे में कोई विवरण नहीं दिया गया था, लेकिन इसमें कहा गया था कि 'सशस्त्र संघर्ष के दौरान, कानून प्रवर्तकों ने छह आतंकवादियों को मार गिराया और उनके कई साथी घायल हो गए।

मलयेशिया के पूर्व नेता नजीब रजाक को 15 साल की जेल और भारी जुर्माना

कुआलालंपुर , एजेंसी। जेल में बंद मलयेशिया के पूर्व प्रधानमंत्री नजीब रजाक को शुक्रवार को 1एमडीबी राज्य निवेश कोष से अरबों डॉलर की लूट से जुड़े उनके सबसे बड़े भ्रष्टाचार मुकदमे में दोषी ठहराए जाने के बाद 15 साल की सजा और 13.5 अरब रिंगिट (3.3 अरब अमेरिकी डॉलर) का भारी जुर्माना और संपत्ति जब्त करने का आदेश दिया गया। देश के उच्च न्यायालय ने 72 वर्षीय नजीब को सत्ता के दुरुपयोग के चार मामलों और vMDB फंड से उनके व्यक्तिगत बैंक खातों में स्थानांतरित किए गए 700 मिलियन अमेरिकी डॉलर से अधिक की धनराशि से संबंधित मनी लॉन्ड्रिंग के 21 आरोपों में दोषी पाया। न्यायमूर्ति कॉलिन लॉरेंस सेक्वेरा ने नजीब को सत्ता के दुरुपयोग के प्रत्येक आरोप के लिए 15 साल और मनी लॉन्ड्रिंग के प्रत्येक आरोप के लिए पांच साल की जेल की सजा सुनाई। ये सजाएं साथ-साथ चलेंगी, जिसका मतलब है कि उसे 15 साल और जेल में बिताने होंगे। जज ने कहा कि नई सजा 1स्छक्रमामले में उसकी मौजूदा सजा खत्म होने के बाद शुरू होगी। उन्होंने सत्ता के दुरुपयोग के आरोपों के लिए नजीब पर कुल 11.4 अरब रिंगिट (2.8 अरब अमेरिकी डॉलर) का जुर्माना लगाया।

जापान में 50 से ज्यादा गाड़ियां टकराईं : कई गाड़ियां जलकर खाक

टोक्यो, एजेंसी। जापान में शुक्रवार देर रात बर्फीले मौसम के कारण बड़ा सड़क हादसा हुआ है। पुलिस के मुताबिक, कोहरे के कारण इलाके में विजिबिलिटी कम थी, जिसके चलते दो ट्रक आपस में टकरा गए। टक्कर के बाद एक्सप्रेसवे का एक हिस्सा ब्लॉक हो गया। पीछे से आ रही गाड़ियां बर्फीली सड़क पर समय रहते ब्रेक नहीं लगा सकीं और देखते ही देखते 50 से ज्यादा गाड़ियां आपस में भिड़ गए। टक्कर के बाद गाड़ियों में आग लग गई। हादसा गुन्मा प्रान्त के मिनाकामी कस्बे में कान-एत्सु एक्सप्रेसवे पर हुआ। इसमें 77 साल की बुजुर्ग महिला की मौत हो गई, जबकि 26 लोग घायल हो गए। हादसे के वक्त देश में साल के अंत और नए साल की छुट्टियों को लेकर भारी ट्रैफिक था। पुलिस ने बताया कि घायलों में से पांच की हालत गंभीर है। हादसे के बाद एक गाड़ी में आग लग गई। जो तेजी से फैलते हुए एक दर्जन से ज्यादा गाड़ियों तक पहुंच गई। कई वाहन पूरी तरह जलकर राख हो गए हैं। आग बुझाने में दमकल कर्मियों को करीब सात घंटे लगे। पुलिस जांच, मलबा हटाने और सड़क की सफाई के चलते एक्सप्रेसवे के कुछ हिस्से अभी भी बंद हैं।

ढाका में मदरसे में धमाका, बम बनाने का सामान बरामद

ढाका , एजेंसी। बांग्लादेश की राजधानी ढाका के दक्षिण केरानीगंज इलाके के हासनाबाद में स्थित उम्माल कुरा इंटरनेशनल मदरसा में शुक्रवार को धमाका हुआ। इसकी वजह से मदरसे के एक कमरे की दीवारें और छत पूरी तरह ढह गईं। घटना के बाद इलाके में अफरा-तफरी मच गई। सूचना मिलने पर पुलिस और सुरक्षा एजेंसियां मौके पर पहुंचीं। तलाशी के दौरान वहां से बम बनाने में इस्तेमाल होने वाला सामान बरामद किया गया है। हालांकि धमाके में किसी के हताहत होने की पुष्टि नहीं हुई है। पुलिस का कहना है कि यह धमाका किस उद्देश्य से किया गया, इसकी जांच की जा रही है।

ट्रंप की वापसी से लेकर नेपाल में ओली के तख्तापलट तक, दुनिया में 2025 के बड़े राजनीतिक बदलाव

वाशिंगटन, एजेंसी। साल 2025 वैश्विक स्तर पर राजनीतिक बदलाव के साथ ही सियासी उथल-पुथल का वर्ष साबित हुआ है। जहां एक ओर सत्ता के पुराने केंद्र डगमगाए, वहीं दूसरी ओर वैश्विक सियासत में नए ध्रुवों ने आकार लिया। साल की शुरुआत पश्चिम में अमेरिका में लोकतांत्रिक तरीके से हुए सत्ता परिवर्तन से लेकर पूरब में जेन-ज़ी प्रदर्शनकारियों के हिंसक प्रदर्शनों से नेपाल में हुए केपी शर्मा ओली के तख्तापलट तक तमाम सियासी बदलाव इसमें शामिल हैं। आइए 2025 में दुनियाभर में हुए तमाम बड़े राजनीतिक बदलावों पर एक नजर डालते हैं।

अमेरिका में ट्रंप की वापसी से फैली दुनियाभर में बेचैनी : अमेरिका में हुए चुनाव में डोनाल्ड ट्रंप की वापसी भले ही दिसंबर, 2024 में तय हो गई थी, लेकिन आधिकारिक तौर पर जनवरी, 2025 में उन्होंने राष्ट्रपति के तौर पर सत्ता संभाली। ट्रंप 'मेक अमेरिका ग्रेट अगेन' (मागा) अभियान के दम पर सत्ता में वापस आए। राष्ट्रपति बनने के साथ ही डोनाल्ड ट्रंप ने दुनियाभर के देशों पर पारस्परिक टैरिफ लगाने का एलान किया। अमेरिका की ओर से लगाए गए इस टैरिफ की जद में मित्र देशों से लेकर प्रतिद्वंदी भी शामिल थे। इस पूरे साल में ट्रंप की ओर से कई देशों के आंतरिक मुद्दों में खुद को मुख्य सुलहकर्ता के तौर पर पेश किया गया। इनमें भारत और पाकिस्तान के बीच छिड़े युद्ध को कथित तौर पर रुकवाने का

श्रेय लेना भी शामिल है। ट्रंप ने दावा किया कि अमेरिका की ओर से लगाए गए टैरिफ की वजह से दुनिया में करीब आठ युद्ध उन्होंने रुकवा दिए।

2025 में व्हाइट हाउस की ओर से लिए गए हर फैसले का असर यूक्रेन से लेकर ताइवान तक महसूस किया गया है। एच1-बी वीजा के शुल्क में बढ़ोतरी हो या यूक्रेन को हथियारों की मदद रोकने का एलान या फिर ताइवान को चीन से लोहा लेने के लिए हथियारों की खेप देने का फैसला, हर जगह ट्रंप की नीतियों ने सियासी उथल-पुथल को बढ़ावा दिया। ट्रंप ने अपने फैसलों से सहयोगियों पर दबाव बनाया और प्रतिद्वंद्वियों पर सख्ती बरती। हालांकि, तेजी से बदलती विश्व व्यवस्था के चलते ट्रंप को चीन पर लगाया गया भारी-भरकम टैरिफ टालना पड़ा। आसान शब्दों में कहें तो ट्रंप के शासनकाल में अमेरिका दुनिया का स्थिर स्तंभ नहीं, बल्कि एक अस्थिर धुरी बनता जा रहा है।

ट्रूडो को छोड़नी पड़ी कुर्सी, वजह ट्रंप ही बने : कनाडा के प्रधानमंत्री जस्टिन ट्रूडो ने जनवरी, 2025 में अपने पद से इस्तीफा दे दिया। ट्रूडो के सत्ता से बाहर होने की प्रमुख वजह उनकी पार्टी में हुई आंतरिक बगावत को माना जाता है। हालांकि, इसके सियासी परिदृश्य में कहीं न कहीं अमेरिकी सत्ता में ट्रंप की वापसी भी एक बड़ी वजह रही है। ट्रंप ने अमेरिकी चुनाव जीतने के बाद से ही जस्टिन ट्रूडो पर निशाना साधना शुरू कर दिया था। कभी ट्रंप कनाडा पर 25 फीसदी टैरिफ लगाने की धमकी देते तो कभी कनाडा को अमेरिका का 51वां राज्य बताते हुए ट्रूडो को वहां का गवर्नर बताने लगते थे। इतना ही नहीं जस्टिन ट्रूडो के इस्तीफे का श्रेय भी ट्रंप ने लिया। उन्होंने दावा किया था कि अमेरिका के टैरिफ लगाने के दबाव के चलते ट्रूडो ने इस्तीफा दिया। दरअसल, ट्रंप के आगे ट्रूडो काफी कमजोर नजर आने लगे थे। उन्होंने ट्रंप की तमाम बयानबाजियों पर चुप्पी साधे रखी और इसी के चलते ट्रूडो की अपनी ही पार्टी में उनके खिलाफ बगावत शुरू हो गई। मंत्रियों के इस्तीफों से शुरू हुआ सिलसिला आखिर में ट्रूडो के इस्तीफे तक जा पहुंचा। ट्रूडो के इस्तीफे के बाद हुए चुनावों में मार्क कार्नी की लिबरल पार्टी को जीत मिली और उन्होंने पीएम पद संभाला।

फ्रेडरिक मर्ज बने जर्मनी के नए चांसलर, ओलाफ स्कोल्ज को दी पटखनी : फरवरी, 2025 में जर्मनी की सत्ता में एक बड़ा परिवर्तन देखने को मिला। जर्मनी के चांसलर ओलाफ स्कोल्ज सत्ता से बाहर हो गए और फ्रेडरिक मर्ज नए चांसलर बने। जर्मन राजनीति में उन्हें बुंडेस्टैग में जरूरी बहुमत हासिल करने के लिए दूसरे मतदान की आवश्यकता पड़ी। इसके बाद फ्रेडरिक मर्ज की क्रिश्चियन डेमोक्रेटिक यूनियन (सीडीयू), क्रिश्चियन सोशल यूनियन (सीएसयू) और सोशल डेमोक्रेट्स (एसपीडी) ने जर्मनी की नई सरकार के रूप में काम शुरू किया। चौंकाने वाली बात थी कि 69 वर्षीय मर्ज ने कभी भी महत्वपूर्ण नेतृत्व जिम्मेदारियों वाला कोई शीर्ष सरकारी पद नहीं संभाला था। वे किसी छोटे शहर के मेयर तक नहीं रहे हैं।

कहा जा सकता है कि जर्मनी में चांसलर ओलाफ स्कोल्ज के सत्ता से बाहर होने की जमीन डोनाल्ड ट्रंप की वापसी और उनकी नीतियों से तैयार हुई। ट्रंप की अमेरिका फर्स्ट नीति, नाटो को लेकर सख्त रुख और यूरोप से सुरक्षा खर्च बढ़ाने की मांग ने जर्मन राजनीति पर दबाव बढ़ाया। स्कोलज की सरकार पहले से ही आर्थिक मंदी, ऊर्जा संकट और यूक्रेन युद्ध को लेकर घरेलू आलोचना झेल रही थी। ट्रंप की ओर से रूस के लिए नरम रुख और यूक्रेन को समर्थन घटाने के संकेतों ने जर्मनी में सुरक्षा को लेकर चिंता गहरा दी। इसके चलते जर्मन मतदाताओं और सियासी दलों में स्कोल्ज सरकार पर बदलते वैश्विक हालात में देश के हितों की रक्षा कर पाने को लेकर सवाल खड़े होने लगे।

पाकिस्तान में खैबर-पख्तूनख्वा के सीएम के साथ फिर मारपीट: विधानसभा में बदसलूकी

लाहौर, एजेंसी। पाकिस्तान की पंजाब विधानसभा में शुक्रवार को खैबर पख्तूनख्वा के मुख्यमंत्री सोहेल अफरीदी के साथ सुरक्षाकर्मियों ने मारपीट की। उनके प्रतिनिधियों के साथ भी बदसलूकी की गई। घटना का वीडियो सामने आया है। वीडियो में दिख रहा है कि मुख्यमंत्री अफरीदी अपने प्रतिनिधियों के साथ पंजाब असेंबली में घुस रहे हैं, इस दौरान सुरक्षाकर्मी उन्हें रोकने की कोशिश करते हैं, तभी उनके साथी फतेह उल्लाह बुर्की बीच में आ जाते हैं। इसके बाद अफरीदी ने बयान जारी कर कहा- कोई भी लोकतांत्रिक सरकार ऐसा काम नहीं करती है, यह सीधे-सीधे मार्शल लॉ जैसा व्यवहार है। पाकिस्तान में लोकतंत्र खतरे में है।

अफरीदी के प्रतिनिधि के साथ भी मारपीट : गार्ड अफरीदी के प्रतिनिधि बुर्की के साथ मारपीट करते हैं और उन्हें धक्का देकर विधानसभा से बाहर निकालने की कोशिश करते हैं। हालांकि, अन्य अधिकारियों के बचाव में आने के बाद बुर्की को छोड़ दिया जाता है। पाकिस्तानी अधिकारियों के मुताबिक इस दौरान किसी को कोई चोट नहीं आई है। पाकिस्तान के पंजाब में मुस्लिम लीग नून की सरकार है और नवाज शरीफ की बेटी मरियम नवाज मुख्यमंत्री हैं। वहीं, केपी के मुख्यमंत्री सोहेल अफरीदी इमरान खान की पार्टी

पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ से हैं।

अफरीदी बोले- पंजाब में नकली सरकार है : घटना के बाद अफरीदी ने मीडिया से कहा कि लाहौर में हमारे कार्यकर्ताओं के साथ बुरा व्यवहार और उत्पीड़न किया जा रहा है। उनका कहना था कि पंजाब में एक नकली सरकार है, जो सिर्फ एक पार्टी को डराने और धमकाने में लगी है। उन्होंने बताया कि चक्री और मंडी बहाउद्दीन में हमारे कार्यकर्ताओं के रास्ते रोके गए। उनके वाहन रोक दिए गए। कुछ कार्यकर्ताओं को गिरफ्तार किया गया और सांसदों के साथ भी बदसलूकी हुई।

अफरीदी से एक महीने पहले भी मारपीट की गई थी : अफरीदी 1 महीने पहले 28 नवंबर को रावलपिंडी की अडियाला जेल में इमरान से मिलने गए थे, तब भी पुलिस ने उनके साथ मारपीट की थी। पुलिस ने उनके बाल खींचे और जमीन पर गिरा दिया। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक, सीएम सोहेल अफरीदी पर हमले की कार्रवाई सेना के आदेश पर की गई। अफरीदी जिस समय जेल पहुंचे थे।

रूस का कीव पर मिसाइल और ड्रोन हमला, शहरों की बिजली गुल

कीव, एजेंसी। रूस और यूक्रेन के बीच लगभग चार साल से जारी संघर्ष दिन-प्रतिदिन और घातक रूप लेता हुआ दिख रहा है। जहां एक बार फिर यूक्रेन की राजधानी कीव पर 27 दिसंबर की रात को बड़े पैमाने पर मिसाइल और ड्रोन हमला हुआ। शहर और आसपास के इलाकों में कई विस्फोटों की आवाज सुनी गई। यह हमला उस समय हुआ जब अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप और यूक्रेन के राष्ट्रपति वोलोदिमिर जेलेंस्की के बीच रविवार को फ्लोरिडा में होने वाली शांति बैठक की तैयारी चल रही थी। ऐसे में ये कहना गलत नहीं होगा कि चार साल से जारी ये संघर्ष अभी भी दूर-दूर तक थमता हुआ नजर नहीं आ रहा है। बजाय इसके ये संघर्ष और भयावह रूप लेता हुआ दिख रहा है। हां ये अलग बात है कि अमेरिका समेत कई देश इस संघर्ष को थामने की पुरजोर कोशिश कर रहे है। कीव पर हुए हमले की बात करें तो मीडिया रिपोर्टस के अनुसार, रूस ने किंझाल हाइपरसोनिक मिसाइल, चार इस्कैंडर बैलिस्टिक मिसाइल और कई कालिब्र क्रूज मिसाइलें कीव पर दागीं। इसके अलावा कई ड्रोन (यूएवी) शहर और आसपास के इलाकों में देखे गए। वहीं एक बार फिर रूस के हमले में कीव से लगभग 20 किलोमीटर दूर स्थित ब्रावरी नामक शहर में बिजली गायब हो गई। कीव के महापौर विटाली क्लिचको ने लोगों को शेल्टर में रहने की सलाह दी। यूक्रेन की एयर फोर्स ने भी नागरिकों को सतर्क रहने की चेतावनी जारी की। इससे पहले जेलेंस्की ने शुक्रवार को कहा था कि ट्रंप के साथ बैठक से शांति समझौते की दिशा में कदम बढ़ सकते हैं। यूक्रेनी और अमेरिकी अधिकारियों द्वारा तैयार किया गया 20-बिंदुओं का शांति प्लान लगभग 90% तैयार है। बैठक में यूक्रेन की सुरक्षा और सहयोगियों की भूमिका पर खास जोर होगा। दूसरी ओर, ट्रंप ने कहा कि कोई भी शांति समझौता उनकी मंजूरी के बिना लागू नहीं होगा। वहीं दूसरी ओर इस शांति वार्ता को लेकर रूस के रक्षा मंत्रालय ने कहा कि उसके बलों ने दक्षिणी यूक्रेन में मोर्चों पर आगे बढ़ना जारी रखा और जारोरिज्जिया क्षेत्र के कोसोव्त्सेवो कस्बे पर कब्जा किया।

बांग्लादेशी गायक जेम्स के कॉन्सर्ट पर भीड़ ने किया हमला, बरसाए पत्थर

ढाका, एजेंसी। बांग्लादेश के दिग्गज गायक जेम्स के फरीदपुर में होने वाले एक कार्यक्रम में शुक्रवार की रात को भीड़ ने हमला कर दिया। आयोजकों की ओर से पूरी तैयारियों के बावजूद भीड़ के पत्थर बरसाने और हमला करने के बाद कार्यक्रम को रद्द कर दिया गया। डेली स्टार की रिपोर्ट के मुताबिक गायक जेम्स का कॉन्सर्ट शुक्रवार को रात करीब 9 बजे फरीदपुर जिला स्कूल परिसर में स्कूल की 185वीं वर्षगांठ के मौके पर आयोजित किया जाना था। आयोजन समिति के मुताबिक प्रवेश देने से मना किए जाने के बाद बाहरी लोगों के एक समूह ने कार्यक्रम स्थल में जबरन घुसने का प्रयास किया।

हमलावरों ने की पत्थरबाजी, मंच पर कब्जा करने की कोशिश : इन लोगों ने रोके जाने पर कथित तौर से ईंट-पत्थर फेंकना शुरू कर दिया। भीड़ ने मंच पर कब्जा करने की कोशिश की। फरीदपुर जिला स्कूल के छात्रों ने हमले का विरोध किया, जिसकी वजह से हमलावरों को पीछे हटना

पड़ा। रात करीब 10 बजे आयोजन समिति के संयोजक मुस्तफिजुर रहमान शमीम ने फरीदपुर के पुलिस उपायुक्त के निर्देश पर संगीत कार्यक्रम रद्द करने का एलान किया। समिति के राजिबुल हसन खान ने बीडीन्यूज24 को बताया, 'हमने जेम्स के संगीत कार्यक्रम को सफल बनाने के लिए सभी तैयारियां पूरी कर ली थीं। लेकिन हमें अभी भी समझ नहीं आ रहा है कि हमला क्यों हुआ, इसकी वजह क्या थी या इसके पीछे कौन था।' उन्होंने आगे बताया कि घटना के दौरान ईंटों की चपेट में आने से फरीदपुर जिला स्कूल के कम से कम 15 से 20 छात्र घायल हो गए।

कौन हैं बांग्लादेश के गायक जेम्स : फारुक महफूज अनम को जेम्स के नाम से जाना जाता है। जेम्स बांग्लादेश के गायक-गीतकार, गिटारवादक और संगीतकार हैं। उन्होंने कई हिंदी फिल्मों में भी गाने गाए हैं, जैसे फिल्म 'गैंगस्टर' का 'भीगी भीगी' और फिल्म 'लाइफ इन ए मेट्रो' का 'अलविदा'। वे बांग्लादेश में बेहद लोकप्रिय हैं।

तस्लीमा नसरीन ने की हमले की निंदा : बांग्लादेश की निर्वासित लेखिका तस्लीमा नसरीन ने इस घटना के बारे में लिखते हुए बांग्लादेश में पनप रहे इस चलन की कड़ी निंदा की। सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर एक पोस्ट में तस्लीमा नसरीन ने कहा, 'सांस्कृतिक केंद्र छायानाट को जलाकर राख कर दिया गया है। उदिची - वह संगठन जिसका गठन संगीत, रंगमंच, नृत्य, कविता पाठ और लोक संस्कृति को बढ़ावा देकर धर्मनिरपेक्ष और प्रगतिशील चेतना को पोषित करने के लिए किया गया था - उसे भी जलाकर राख कर दिया गया है। आज जिहादियों ने मशहूर गायक जेम्स के एक कार्यक्रम को रोक दिया। वह ढाका में कार्यक्रम प्रस्तुत किए बिना भारत लौट गए और कहा कि जब तक कलाकार, संगीत और सांस्कृतिक संस्थान सुरक्षित नहीं हो जाते, तब तक वे बांग्लादेश नहीं आएंगे। स्थिति बेकाबू होते देख फरीदपुर जिला प्रशासन ने हस्तक्षेप किया। रात करीब 10 बजे आयोजन समिति के संयोजक डॉ. मुस्तफिजुर रहमान शमीम ने मंच से ऐलान किया कि कानून-व्यवस्था बनाए रखने के लिए जिला उपायुक्त के निर्देश पर जेम्स का कॉन्सर्ट रद्द किया जा रहा है।

फिर 'तत्काल' युद्धविराम पर सहमत हुए थाइलैंड और कंबोडिया, इस साल दूसरी बार हुआ समझौता

बैंकाक, एजेंसी। थाइलैंड और कंबोडिया ने लंबे समय से चले आ रहे सीमा विवाद में चल रहे घमासान लड़ाई को समाप्त करने के लिए शनिवार को एक संयुक्त बयान पर हस्ताक्षर किए, जिसमें 'तत्काल युद्धविराम' की घोषणा की गई। यह युद्धविराम आज दोपहर 12 बजे (स्थानीय समय) से प्रभावी हो गया। दोनों देशों के रक्षा मंत्रियों द्वारा हस्ताक्षरित इस समझौते में सभी प्रकार के हथियारों के उपयोग को रोकने, नागरिकों और बुनियादी ढांचे पर हमलों को बंद करने तथा सैन्य ठिकानों पर आक्रमण न करने का प्रावधान है।

यह इस साल दूसरी बार है जब दोनों पड़ोसी देशों ने युद्धविराम पर सहमति जताई है। जुलाई 2025 में भी इसी तरह के सीमा संघर्ष के बाद अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप और मलेशिया की मध्यस्थता से एक युद्धविराम समझौता हुआ था, जो अक्टूबर में मजबूत किया गया था। लेकिन दिसंबर की शुरुआत में फिर से झड़पें शुरू हो गईं, जिससे पुराना समझौता टूट गया।

हालिया घटनाएं : थाइलैंड और कंबोडिया के बीच 800 किलोमीटर लंबी सीमा पर दशकों पुराना विवाद है, जो मुख्य रूप से प्राचीन मंदिरों (जैसे प्रीह विहार और ता मुएन थोम) और औपनिवेशिक काल की सीमा रेखा से जुड़ा है। 1962 में अंतरराष्ट्रीय न्यायालय ने कुछ क्षेत्रों को कंबोडिया का बताया था, लेकिन आसपास के इलाकों पर विवाद बना रहा। इस साल जुलाई में पांच दिनों की भयंकर लड़ाई के बाद युद्धविराम हुआ था। लेकिन 7-8 दिसंबर 2025 से फिर झड़पें शुरू हो गईं। थाइलैंड ने हवाई हमले किए, जबकि कंबोडिया ने रॉकेट और तोपों से जवाब दिया। लड़ाई लाओस के पास जंगली क्षेत्रों से लेकर थाईलैंड की खाड़ी के तटीय प्रांतों तक फैल गई। दोनों पक्षों ने एक-दूसरे पर युद्धविराम उल्लंघन का आरोप लगाया। हालिया संघर्ष में कम से कम 100 लोगों की मौत हुई है, जिसमें सैनिक और नागरिक शामिल हैं। दोनों तरफ से लाखों लोग विस्थापित हुए हैं- थाइलैंड में लगभग 4 लाख और कंबोडिया में 5 लाख से अधिक।

वार्ताओं का सफर

22 दिसंबर: आसियान विदेश मंत्रियों की बैठक में दोनों देश 24 दिसंबर से वार्ता पर सहमत हुए।

24-26 दिसंबर: जनरल बॉर्डर कमिटी (जीबीसी) की बैठकें थाइलैंड के चांथाबुरी प्रांत में हुईं, जहां तनावपूर्ण माहौल में समझौता तैयार हुआ।

27 दिसंबर: रक्षा मंत्री स्तर पर हस्ताक्षर, युद्धविराम प्रभावी। समझौते में सैनिकों की मौजूदा स्थिति को फ्रीज करने, कोई नई तैनाती न करने और नागरिकों की जल्द घर वापसी की बात है। दोनों पक्षों ने एक-दूसरे पर झूठी जानकारी फैलाने से बचने का भी वादा किया है।

बांग्लादेश की ढाका यूनिवर्सिटी में भारत विरोधी प्रदर्शन

इस्लामाबाद, एजेंसी। बांग्लादेश में एक बार फिर भारत विरोधी प्रदर्शन शुरू हो गए हैं। इंकिलाब मंच ने नेता उस्मान हादी की हत्या के खिलाफ न्याय की मांग करते हुए ढाका के शाहबाग इलाके में प्रदर्शन किया। इस दौरान भारत विरोधी नारे भी लगाए गए। जुमा की नमाज के बाद ढाका यूनिवर्सिटी से जुलूस निकाला गया, जो शाहबाग पहुंचकर धरने में बदल गया। प्रदर्शनकारियों ने सड़क जाम कर दी, जिससे इलाके में यातायात ठप हो गया। इंकिलाब मंच का कहना है कि जब तक हादी की हत्या में न्याय नहीं मिलता, तब तक आंदोलन जारी रहेगा। शरीफ उस्मान हादी की पिछले हफ्ते हत्या कर दी गई थी, जिसके बाद देश में एक बार फिर अशांति फैल गई है। प्रदर्शन के दौरान 'आई एम हादी' जैसे नारे गूंजते रहे। ढाका यूनिवर्सिटी वही जगह है, जहां जुलाई 2024 में हुए आंदोलन की रणनीति बनी थी।

बांग्लादेशी हिंदू की हत्या मामले में 6 और गिरफ्तार : बांग्लादेश में दीपू चंद्र दास की बेरहमी से की गई हत्या के मामले में पुलिस ने छह और लोगों को गिरफ्तार किया है। यह गिरफ्तारी मयमनसिंह जिले के भालुका इलाके में छापेमारी के दौरान हुई। ढाका ट्रिब्यून की रिपोर्ट के मुताबिक, इन लोगों पर आरोप है कि वे दीपू दास पर अपनी नौकरी छोड़ने का दबाव बना रहे थे। इस मामले में अब तक कुल 18 लोगों को हिरासत में लिया जा चुका है। दीपू चंद्र दास की 18 दिसंबर को भीड़ ने पीट-पीटकर हत्या कर दी थी। इसके बाद हमलावरों ने उन्हें एक पेड़ से आग भी लगा दी थी। इस घटना के बाद अल्पसंख्यक हिंदू समुदाय ने बड़े पैमाने पर विरोध प्रदर्शन किया था।

हिंदू संगठन ने ढाका में प्रदर्शन किया : इस घटना के विरोध में हिंदू संगठन नेशनल हिंदू महाजोत ने ढाका के नेशनल प्रेस क्लब पर प्रदर्शन किया। प्रदर्शनकारियों ने दीपू दास की हत्या की निंदा की और मांग की कि दोषियों को कड़ी सजा दी जाए। उन्होंने यह भी कहा कि बांग्लादेश में अल्पसंख्यक हिंदुओं पर हमले बढ़ रहे हैं और सरकार को उनकी सुरक्षा के लिए ठोस कदम उठाने चाहिए। बांग्लादेश में बढ़ती हिंसा को लेकर अंतरराष्ट्रीय स्तर पर भी चिंता जताई जा रही है।

इजरायल ने सोमालिलैंड को दे दी देश के रूप में मान्यता, भड़का अफ्रीकी संघ; क्या मामला?

तेल अवीव, एजेंसी। इजरायल ने शुक्रवार को औपचारिक रूप से सोमालिलैंड को एक स्वतंत्र देश के रूप में मान्यता दे दी है। इजरायल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू ने सोमालिया से अलग हुए इस देश को मान्यता देने के का ऐलान करते हुए यहां के राष्ट्रपति अब्दिरहमान मोहम्मद अब्दुल्लाही को इजरायल के आधिकारिक दौरे का न्यौता भी दिया। गौरतलब है कि यह देश सोमालिया में चल रहे गृहयुद्ध के बाद अलग हुआ है, यह काफी समय से एक अलग देश के रूप में अपनी सत्ता चला रहा है। वहीं, दूसरी ओर अफ्रीकी संघ ने इजरायल के इस फैसले का विरोध किया है। टाइम्स ऑफ इजरायल की एक रिपोर्ट के अनुसार सोमालिया से अलग हुए इस क्षेत्र को 30 साल से अधिक समय के बाद किसी देश ने आधिकारिक तौर पर मान्यता दी है। इस ऐतिहासिक घोषणा पत्र पर प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू और इजरायली विदेश मंत्री गिदेओन साआर ने हस्ताक्षर किए, जबकि सोमालिलैंड की तरफ से राष्ट्रपति अब्दुल्लाही ने। दोनों ही नेताओं ने इस मान्यता पत्र को ऐतिहासिक पल बताया। नेतन्याहू ने कहा कि इस क्षण से दोनों देशों के बीच में ऐतिहासिक मित्रता की शुरुआत होती है। दोनों देश आर्थिक क्षेत्रों , कृषि और सामाजिक विकास जैसे क्षेत्रों में साथ मिलकर काम करेंगे। इजरायल का यह फैसला अमेरिका के राष्ट्रपति ट्रंप के पहले कार्यकाल में हुए अब्राहम अकॉर्ड की भावनाओं के अनुरूप है। इजरालय से मान्यता मिलने के बाद सोमालिलैंड ने कहा है कि वह भी इस समझौते में शामिल होना चाहता है। राष्ट्रपति ने एक्स पर अपनी खुशी जाहिर करते हुए लिखा कि यह दोनों देशों की रणनीतिक साझेदारी की शुरुआत है। उन्होंने कहा, 'यह एक ऐतिसाहिक क्षण है। हम इसका गर्मजोशी के साथ स्वागत करते हैं।' सोमालिलैंड की राजधानी हरगेसा में भी लोगों ने इजरायल के इस कदम का स्वागत किया और सड़कों पर आकर जश्न मनाया। अफ्रीकी संघ, सोमालिया समेत कई देशों ने जताई आपत्ति

इजरायल की नेतन्याहू सरकार के इस फैसले की कई देशों ने निंदा की है। सोमालिया ने इसे उसकी संप्रभुता पर जानबूझकर किया गया हमला बताया। सोमालिया के विदेश मंत्री ने कहा कि इस फैसले की वजह से क्षेत्र की शांति कमजोर होगी। वहीं, अफ्रीकी संघ ने कड़े शब्दों में इसकी निंदा करते हुए इस कदम को पूरी तरह से खारिज कर दिया। उन्होंने कहा कि सोमालिलैंड नामक क्षेत्र अफ्रीकी महासंघ के सदस्य सोमालिया का अभिन्न हिस्सा है। उन्होंने कहा, 'सोमालिया की एकता, संप्रभुता और क्षेत्रीय अखंडता को कमजोर करने की कोई भी कोशिश एक खतरनाक मिसाल का काम कर सकती है, जिससे पूरे महाद्वीप की शांति और स्थिरता पर दूरगामी प्रभाव होगा। गृहयुद्ध से जूझ रहे सोमालिया के मुख्य सहयोगी तुर्किए ने इजरायल के इस फैसले का विरोध किया है। तुर्किए के विदेश मंत्रालय ने कहा कि इजरायल की यह पहल उसकी विस्तारवादी नीति से मेल खाती है। यह सोमालिया के आंतरिक मामलों में खुला हस्तक्षेप है। तुर्किए सोमालिया की एकता, संप्रभुता और क्षेत्रीय अखंडता के प्रति पूरी तरह प्रतिबद्ध है।

क्या है सोमालिलैंड की कहानी : अफ्रीकी महाद्वीप के हॉर्न पर बसे सोमालिया के अंतर्गत माने जाने वाले सोमालिलैंड को मान्यता देने वाला इजरायल पहला देश बना है। अभी तक इस क्षेत्र को किसी भी देश ने स्वतंत्र देश की मान्यता नहीं दी है। हालांकि, ब्रिटेन इथियोपिया, तुर्किए, यूएई,डेनमार्क, कीनिया और ताइवान जैसे देशों के साथ उसके अनौपचारिक राजनयिक संबंध हैं। ऐतिहासिक दृष्टि से 1960 के दशक में सोमालिलैंड को कुछ समय के लिए स्वतंत्रता मिली थी और उस समय इजरायल समेत कुल 35 देशों ने उसे मान्यता दी थी। लेकिन फिर बाद में वह स्वेच्छा से सोमालिया के साथ एकीकृत हो गया था। बाद में जब 1991 में सोमालिया गृहयुद्ध में उलझ गया तो सोमालिलैंड ने फिर से खुद को स्वतंत्र घोषित कर लिया। तब से लेकर अभी तक सोमालिलैंड एक अलग राज्य के रूप में ही काम कर रहा है। इसकी अपनी सरकार, अपनी मुद्रा और सुरक्षा बल है। सोमालिया के लंबे समय से चले आ रहे संघर्ष के विपरीत सोमालिलैंड में अपेक्षाकृत शांत और स्थिर शासन देखने को मिलता है। इजरायल का यह फैसला एक सोची समझी रणनीति का हिस्सा है। विश्लेषकों के अनुसार, सोमालिलैंड की भौगोलिक स्थिति महत्वपूर्ण है। रेड सी के पास इजरायल को साझेदारों की जरूरत है। इन साझेदारों की मदद से वह भविष्य में यमन के हूती विद्रोहियों के खिलाफ कार्रवाई कर सकता है।

स्वामी,मुद्रक व् प्रकाशकः सुरेश मौर्या द्वारा अष्ठ विनायक ओफ़्सेट एफपी,149 प्लोट 26 खोडीयारनगर,सिद्धिविनायक मंदीर के पास ,भाटेना) हो.सो अंजना सुरत गुजरात से मुद्रित एवं 191 महादेव नगर उधना सुरत गुजरात से प्रकाशित संपादक : सुरेश मौया (M) 9879141480 RNI No.:GUJHIN/2018/75100 (Subject to Surat jurisdiction)

Web site : www.krantisamay.com & epaper.krantisamay.com www.facebook.com/krantisamay1 www.twitter.com/krantisamay1

सेना की फायरिंग रेंज में ब्लास्ट में चार जवान घायल, दो की हालत गंभीर

सहारनपुर (एजेंसी)। मिर्जापुर क्षेत्र स्थित सेना की फायरिंग रेंज में नियमित अभ्यास के दौरान अचानक हुए ब्लास्ट में चार जवान घायल हो गए। धमाके की आवाज सुनते ही इलाके में अफरा-तफरी मच गई और अभ्यास रोक दिया गया। घटना के तुरंत बाद घायल जवानों को सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र ले जाया गया, जहां डॉक्टरों की टीम ने प्राथमिक उपचार किया। बेहट सीएचसी के चिकित्सकों के मुताबिक चारों जवानों को चोटें आई हैं, जिनमें से दो की हालत गंभीर है। गंभीर रूप से घायल जवानों को जिला अस्पताल रेफर किया है, जबकि अन्य दो जवानों का इलाज वहीं किया जा रहा है। घटना की सूचना मिलते ही सेना के वरिष्ठ अधिकारी मौके पर पहुंचे और हालात का जायजा लिया। इसके साथ ही स्थानीय पुलिस भी फायरिंग रेंज पर पहुंची और सुरक्षा व्यवस्था कड़ी कर दी गई। राहत और बचाव कार्य तेजी से चलाया गया, ताकि किसी और अनहोनी से बचा जा सके। सुरक्षा कारणों से पूरे क्षेत्र को अस्थायी रूप से सील कर दिया। जिला अस्पताल प्रशासन ने भी इमरजेंसी वार्ड को अलर्ट मोड पर रखा। अतिरिक्त डॉक्टर और पैरामेडिकल स्टाफ तैनात किए गए ताकि घायल जवानों को तुरंत और बेहतर चिकित्सा सुविधा मिल सके। गंभीर जवानों का इलाज विशेषज्ञ डॉक्टरों की निगरानी में चल रहा है। शुरुआती जानकारी के मुताबिक हादसा तब हुआ जब फायरिंग रेंज में नियमित ट्रेनिंग चल रही थी। अचानक हुए ब्लास्ट में चार जवान घायल हो गए। हालांकि, ब्लास्ट के कारणों की आधिकारिक पुष्टि अभी नहीं हुई है। सेना के अधिकारियों ने बताया कि सभी घायल जवानों का इलाज किया जा रहा है और उनकी स्थिति पर लगातार नजर रखी जा रही है। घटना के कारणों की जांच के आदेश दे दिए गए हैं। जांच पूरी होने के बाद ही यह साफ होगा कि हादसा तकनीकी खराबी, मानवीय चूक या किसी अन्य कारण से हुआ।

नए साल के स्वागत के लिए दिल्ली तैयार... 20,000 जवान पर रहेगी सुरक्षा की जिम्मेदारी

नई दिल्ली (एजेंसी)। नए साल के स्वागत के लिए दिल्ली पूरी तरह तैयार है, लेकिन इस दौरान सुरक्षा और कानून-व्यवस्था बनाए रखने के लिए दिल्ली पुलिस ने विशेष तैयारी की हैं। पुलिस अधिकारियों ने बताया कि शराब पीकर गाड़ी चलाने और यातायात नियमों का उल्लंघन करने वालों पर इस बार कड़ी नजर रहेगी। नए साल की पूर्व संध्या पर दिल्ली की सड़कों, बाजारों और मॉल के आसपास दिल्ली पुलिस, ट्रैफिक पुलिस और अर्धसैनिक बलों के लगभग 20,000 जवान तैनात रहने वाले है। हरियाणा और उत्तर प्रदेश से आने वाली भीड़ को देखते हुए दिल्ली की सीमाओं पर सुरक्षा बढ़ा दी गई है। प्रवेश द्वारों पर हर वाहन की जांच होगी। कनॉट प्लेस, हौज खास और प्रमुख शॉपिंग मॉल्स के आसपास विशेष नाकेबंदी की गई है। रणनीतिक स्थानों पर त्वरित प्रतिक्रिया टीमें (क्यूआरटी) तैनात रहेंगी। ट्रैफिक पुलिस ने खतरनाक ड्राइविंग और स्टंटबाजी रोकने के लिए सख्त योजना तैयार की है। शराब पीकर गाड़ी चलाने वालों की पहचान के लिए पुलिस बड़े पैमाने पर ब्रेथ एनालाइजर का उपयोग करेगी। पुलिस अधिकारियों ने साफ किया है कि शराब पीकर वाहन चलाने या खतरनाक स्टंट करने पर वाहन को तुरंत जब्त किया जाएगा। कनॉट प्लेस के इनर सर्कल में केवल वैध स्टिकर वाले वाहनों को ही प्रवेश की अनुमति मिलेगी। सुरक्षा के मद्देनजर पुलिस होटल, गेस्ट हाउस और रैन बसेरों की लगातार चेकिंग कर रही है। बस स्टैंड और रेलवे स्टेशनों पर भी विशेष अभियान चलाया जा रहा है ताकि किसी भी संदिग्ध व्यक्ति या गतिविधि की पहचान की जा सके। सभी थाना प्रभारियों को पूरी रात सड़कों पर रहने के निर्देश दिए गए हैं।

स्टॉक और आईपीओ से पैसा होगा डबल.....कहकर लगा दिया 16 लाख रुपये का चूना

गांधीनगर (एजेंसी)। गुजरात के कच्छ जिले में साइबर ठगी का चौंकाने वाला मामला सामने आया है, जिसमें एक शख्स ने फेक स्टॉक और आईपीओ में निवेश कर अपनी पूरी कमाई, करीब 16 लाख रुपये, गंवा दी। यह धोखाधड़ी वाटसएप के जरिए हुई, जहां पीड़ित को एक प्रोफेशनल निवेश ग्रुप में शामिल किया गया। शामिल करने के बाद ग्रुप में उन्हें कई फेक दावे दिखाए गए और बताया गया कि स्टॉक मार्केट और आईपीओ में निवेश करके मोटी कमाई की जा सकती है। जुलाई में पीड़ित को एक लिंक भेजा गया, जिसमें ऑनलाइन फॉर्म भरने और एक एप इंस्टॉल करने को कहा गया। शुरुआत में विक्टिम ने 5,000 रुपये निवेश किए और 5,245 रुपये का रिटर्न देखा, जिससे उनका विश्वास बढ़ गया और उन्होंने और पैसे निवेश करना शुरू किया। साइबर ठगों ने अलग-अलग बैंक खातों में रुपये जमा कराए और कुल 16 लाख रुपये ट्रांसफर करवा लिए। बाद में, पीड़ित के वॉलेट में 18 लाख रुपये का लोन दिखाई दिया, जिससे वह हैरान रह गए। जब उन्होंने पैसे निकालने की कोशिश की, तब उन्हें प्रोसेसिंग फीस के नाम पर अतिरिक्त 9 लाख रुपये की डिमांड की गई। इस घटना के बाद पीड़ित को धोखाधड़ी का शक हुआ और उन्होंने पुलिस में शिकायत दर्ज कराई। इसके बाद गुजरात पुलिस ने मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। विशेषज्ञों का कहना है कि इसतरह के निवेश ग्रुप्स में शामिल होने और जल्दी अमीर बनने के लालच में आने से बचना चाहिए। यह साइबर ठगों की पुरानी और आम चाल है, जिसमें बहुत से लोग फंस चुके हैं। इसतरह के मामले चेतावनी हैं कि ऑनलाइन निवेश और कमाई के झांसे में सावधानी बरतनी बेहद जरूरी है।

छात्रों के प्रस्तावित विरोध प्रदर्शन में शामिल होने वाले नेता नजरबंद... महबूबा, इल्तिजा और रुहुल्लाह मेहदी

जम्मू (एजेंसी)। जम्मू कश्मीर में मौजूदा आरक्षण नीति के खिलाफ छात्रों के प्रस्तावित विरोध प्रदर्शन में शामिल होने से रोकने के लिए पीपुल्स डेमोक्रेटिक पार्टी (पीडीपी) अध्यक्ष और पूर्व सीएम महबूबा मुफ्ती और नेशनल कांफ्रेंस के सांसद आगा सैयद रुहुल्लाह मेहदी सहित कई नेताओं को नजरबंद किया गया। अधिकारियों ने बताया कि महबूबा मुफ्ती, उनकी बेटी इल्तिजा मुफ्ती, श्रीनगर से लोकसभा सदस्य रुहुल्लाह मेहदी, पीडीपी नेता वहीद पारा और श्रीनगर के पूर्व महापौर जुनैद मट्टू को उनके घरों में नजरबंद किया गया। जिला प्रशासन ने कदम इन नेताओं द्वारा उन छात्रों के साथ एकजुटता व्यक्त प्रकट करने के बाद उठाया, जिन्होंने गुपकर रोड पर शांतिपूर्ण विरोध प्रदर्शन करने की योजना बनाई थी। इन नेताओं ने मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला द्वारा मुद्दे के समाधान के लिए समिति गठित करने के एक साल पूरे होने के बावजूद कोई सकारात्मक नतीजा नहीं निकलने पर छात्रों की ओर से आयोजित मार्च में शामिल होने की बात कही थी।

विवाद बढ़ने पर दिग्विजय सिंह की सफाई...

गोडसे की विचारधारा से कुछ सीखने की जरूरत नहीं

नई दिल्ली(एजेंसी)। कांग्रेस के वरिष्ठ नेता और मध्य प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री दिग्विजय सिंह ने हाल ही में राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ (आरएसएस) और भाजपा के संगठनात्मक ढांचे की प्रशंसा कर राजनीतिक गलियारों में हलचल पैदा कर दी थी। लेकिन अब उन्होंने अपने बयान पर सफाई दी है। उन्होंने स्पष्ट किया कि विचारधारा के स्तर पर वे अब भी संघ के धुर विरोधी हैं और गांधी के हत्यारे गोडसे की विचारधारा से कांग्रेस को कुछ भी सीखने की जरूरत नहीं है।

दरअसल विवाद की शुरुआत तब हुई जब दिग्विजय ने आरएसएस के अनुशासन और जमीनी कार्यकर्ताओं को शीर्ष पदों तक पहुंचाने की क्षमता की सराहना की थी। अपनी सफाई में उन्होंने कहा, मैंने जो कहना था, कह दिया। मैं पिछले 50 सालों से कांग्रेस में हूं और मैंने विधानसभा से लेकर संसद तक इन सांप्रदायिक ताकतों के खिलाफ लड़ाई लड़ी है। मैं भाजपा-आरएसएस की विचारधारा का हमेशा विरोधी रहा हूं और आगे भी इस विचारधारा का विरोधी रहूंगा।

जब सिंह से संघ के अनुशासन के बारे में पूछा गया, तब उन्होंने तीखा हमला कर कहा कि कांग्रेस को गोडसे जैसे हत्यारों के समर्थकों से कुछ भी सीखने की आवश्यकता नहीं है। हालांकि, उन्होंने यह जरूर दोहराया कि किसी भी संगठन को समय-समय पर खुद को मजबूत करने की जरूरत होती है।

बात दें कि दिग्विजय के इस बयान ने कांग्रेस के भीतर भी एक नई बहस छेड़ दी है। पार्टी के वरिष्ठ नेता इस मुद्दे पर अलग-अलग राय रखते हैं। तिरुवनंतपुरम के सांसद शशि थरूर ने दिग्विजय सिंह का बचाव करते हुए कहा कि किसी भी राजनीतिक दल के लिए अनुशासन बेहद जरूरी है। थरूर ने कहा, हमारी पार्टी का 140 साल का लंबा इतिहास है और हम अपने अतीत से बहुत कुछ सीख सकते हैं। मैं भी चाहता हूँ कि हमारा संगठन मजबूत और अनुशासित बने।

वहीं, कांग्रेस प्रवक्ता पवन खेड़ा ने कड़ा रुख दिखाकर कहा कि आरएसएस से सीखने जैसा कुछ नहीं है। उन्होंने सवाल किया कि गोडसे के लिए जाने जाने वाला संगठन भला गांधी द्वारा स्थापित संगठन को क्या सिखा सकता है?

यह विवाद तब शुरू हुआ जब दिग्विजय ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की 1995 की पुरानी तस्वीर साझा की। इस तस्वीर में पीएम मोदी जमीन पर बैठे दिख रहे थे और उनके पास तत्कालीन भाजपा अध्यक्ष एल.के. आडवाणी मौजूद थे। इस फोटो के जरिए दिग्विजय ने संकेत दिया था कि कांग्रेस को यह सीखना चाहिए कि कैसे आरएसएस और भाजपा अपने जमीनी कार्यकर्ताओं को आगे बढ़ने का मौका देती हैं।

कोहरे का कहर : वंदे भारत-दरभंगा हमसफर सहित 60 से ज्यादा ट्रेनों के पहिए थमे

नई दिल्ली। सर्दी और कोहरे से लगभग पूरा उत्तर भारत परेशान है। खासकर कोहरे के कहर ने जहां जनजीवन प्रभावित किया है वहीं ट्रेनों पर भी इसका असर दिखाई दे रहा है। कोहरे के कारण रविवार को भी रेल यात्रियों की परेशानी बनी रही। दिल्ली आने वाली वंदे भारत, राजधानी, शताब्दी, हमसफर सहित लंबी दूरी की 60 से अधिक ट्रेनें दो से 13 घंटे के विलंब से चल रही हैं। वाराणसी-नई दिल्ली वंदे भारत एक्सप्रेस 13.15 घंटे की देरी से चल रही है। देरी से दिल्ली पहुंचने के कारण वापसी दिशा में जाने वाली कई ट्रेनों के प्रस्थान समय में भी बदलाव करना पड़ा है। लंबी दूरी की ट्रेनों के साथ ही कई लोकल ट्रेनें भी आधे घंटे से लेकर एक घंटे की देरी से चल रही हैं।

देरी से चल रही प्रमुख ट्रेनें- नई दिल्ली-सोगरिया (कोटा) सुपरफास्ट एक्सप्रेस, नई दिल्ली-दरभंगा बिहार संपर्क क्रांति एक्सप्रेस, नई दिल्ली-दरभंगा हमसफर विशेष, नई दिल्ली-अमृतसर शान-ए-पंजाब एक्सप्रेस, नई दिल्ली-लखनऊ स्वर्ण शताब्दी एक्सप्रेस, नई दिल्ली-गया महाबोधि एक्सप्रेस, नई दिल्ली-लखनऊ गोमती एक्सप्रेस, हजरत निजामुद्दीन-जबलपुर महाकौशल एक्सप्रेस, हजरत निजामुद्दीन-हुबली सुपरफास्ट एक्सप्रेस, आनंद विहार टर्मिनल-पुरी नीलांचल एक्सप्रेस, आनंद विहार टर्मिनल-जोगबनी सीमांचल एक्सप्रेस, आनंद विहार टर्मिनल-कामाख्या नार्थ ईस्ट एक्सप्रेस।

दिल्ली में सक्रिय 35 हजार नकली डॉक्टर... कार्रवाई के नाम पर एक पर ही एफआईआर दर्ज

नई दिल्ली(एजेंसी)। देश की राजधानी दिल्ली में बिना डिग्री और मेडिकल पढ़ाई के लोगों का इलाज कर रहे नकली डॉक्टरों के खिलाफ कार्रवाई के मामले में दिल्ली मेडिकल काउंसिल (डीएमसी) के उदासीन रवैये का खुलासा हुआ है।बीते दो सालों में दिल्ली में केवल एक नकली डॉक्टर के खिलाफ एफआईआर दर्ज की गई है, जबकि राजधानी में हजारों की संख्या में इसतरह के लोग गलत इलाज कर लोगों की जान से खिलवाड़ कर रहे हैं। रिपोर्ट के अनुसार, साल 2024 में 9 मामलों की जांच की गई, लेकिन एक भी मामले में एफआईआर दर्ज नहीं हुई।

इसकी वजह यह रही कि डीएमसी की ओर से एक भी केस पुलिस को एफआईआर दर्ज कराने के लिए नहीं भेजा गया। वहीं, 2025 में अब तक 22 मामलों की जांच हुई, लेकिन केवल एक केस पुलिस को भेजा गया, जिस पर एफआईआर दर्ज की गई। पिछले पांच सालों में दिल्ली में नकली डॉक्टरों के खिलाफ कुल 22 एफआईआर दर्ज हो सकी है। इस बारे में दिल्ली मेडिकल काउंसिल के एंटी क्रैकरी सेल के अधिकारी ने कहा कि साल 2015 में दिल्ली हाई कोर्ट ने आदेश जारी कर एक कमिटी बनाई थी, जिसे हर महीने दिल्ली में छापेमारी करनी थी। हालांकि, यह रिपोर्ट साफ दिखा रही है कि आदेशों का सही तरीके से पालन नहीं हो रहा है। अनुमान के मुताबिक, दिल्ली में 35 से 40 हजार नकली डॉक्टर सक्रिय हैं, जो इलाज के नाम पर आम जनता को ठग रहे हैं। कई बार गरीब मरीजों को इसकी कीमत अपनी जान देकर चुकानी पड़ती है।

सीएम सरमा ने किया आगाह कहा- असम को बांग्लादेश में मिलाने की हो सकती है कोशिश

गुवाहाटी (एजेंसी)। असम में बांग्लादेश के लोगों की संख्या लगातार बढ़ रही है। यहां इनकी आबादी करीब 40 प्रतिशत हो चुकी है। जिस दिन ये आबादी 50 प्रतिशत का आकड़ा पार कर लेगी उसी दिन से बांग्लादेश का हिस्सा बनाने के प्रयास शुरु हो जाएंगे। यह आशंका असम के मुख्यमंत्री हेमंत विस्वा सरमा ने राज्य की बदलती जनसांख्यिकी को लेकर एक गंभीर चेतावनी जारी की है। भाजपा की राज्य कार्यकारिणी की बैठक के दौरान मुख्यमंत्री ने कहा कि इस स्थिति को असम की अस्मिता और संस्कृति के लिए एक बड़ा खतरा पैदा हो सकता है।

मुख्यमंत्री सरमा ने आंकड़ों का हवाला देते हुए कहा कि वर्तमान में बांग्लादेशी मूल के लोगों की आबादी 40 प्रतिशत को पार कर चुकी है और यह लगातार बढ़ रही है। उन्होंने कहा, आज हम अपनी आंखों से इस वास्तविकता को देख रहे हैं। यदि यह आबादी 50 प्रतिशत से अधिक हो गई, तो असम के अस्तित्व पर संकट मंडराने लगेगा। बांग्लादेश में हाल ही में हुई दीपू दास की मॉब लिंचिंग का जिक्र करते हुए मुख्यमंत्री ने असम के लोगों को आगाह किया। उन्होंने कहा कि अगर आज वहां ऐसी घटनाएं हो रही हैं, तो असम के लोग कल्पना कर सकते हैं कि अगले 20 वर्षों में यहां की स्थिति क्या होगी। उन्होंने घुसपैठियों की वफादारी पर भी सवाल उठाते हुए पूछा कि यदि भारत और बांग्लादेश के बीच युद्ध होता है तो ये लोग किसका साथ देंगे?मुख्यमंत्री ने जनगणना के पुराने आंकड़ों और भविष्य के अनुमानों को साझा करते हुए बताया कि 2011 में मुस्लिम आबादी 34 प्रतिशत थी, जिसमें बांग्लादेशी मूल के मुस्लिम 31 प्रतिशत और स्थानीय मुस्लिम मात्र 3 प्रतिशत थे। 2027 तक यह संख्या बढ़कर 40 प्रतिशत होने का अनुमान है। स्वदेशी आबादी गिरकर 60 प्रतिशत पर आ गई है और इसमें और गिरावट की आशंका है। उन्होंने भावुक होते हुए कहा कि उनके जीवनकाल में घुसपैठियों की आबादी 21 प्रतिशत से बढ़कर 40 प्रतिशत हो गई है और उनके बच्चों के समय तक असमिया समुदाय की आबादी सिमटकर मात्र 30 प्रतिशत रह सकती है। आगामी विधानसभा चुनावों को मुख्यमंत्री ने महज एक राजनीतिक मुकाबला न मानकर सभ्यता की लड़ाई करार दिया। उन्होंने कांग्रेस पर दशकों तक तुष्टिकरण की राजनीति करने का आरोप लगाया, जिसके कारण राज्य में एक नई सभ्यता विकसित हो गई है। इनकी संख्या अब लगभग 1.5 करोड़ तक पहुंच चुकी है। सरमा ने कहा कि यह लड़ाई अपनी भूमि (माटी), पहचान (जाति) और आधार (भेटी) को बचाने की है। उन्होंने भाजपा को असम के लिए उम्मीद की आखिरी किरण बताते हुए कहा कि पार्टी राज्य को घुसपैठियों के कारण पैदा होने वाले अंधेरे के गर्त में गिरने से बचाएगी।

मुख्यमंत्री ने असम को शंकर-अजान (वैष्णव संत शंकरदेव और सूफी संत अजान फकीर) की धरती बताने वाली धारणा को सिरे से खारिज कर दिया। उन्होंने स्पष्ट रूप से कहा कि असम केवल शंकर-माधव (शंकरदेव और उनके शिष्य माधवदेव) की भूमि है। उन्होंने कहा कि अजान फकीर के साथ महापुरुषों की तुलना करके हमारी सांस्कृतिक पहचान को कमजोर करने की कोशिशों को बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। अपने संबोधन के अंत में उन्होंने अहोम सेनापति लाचित बोरफुकन का स्मरण किया, जिन्होंने बीमार होने के बावजूद मुगलों को हराया था।

कोगिलू गांव में तोड़फोड़ की कार्रवाई ने कांग्रेस के अंदर मचा दी खलबली

-आलाकमान ने कर्नाटक सरकार को संयम और संवेदनशीलता बरतने की दी

नई दिल्ली (एजेंसी)। कर्नाटक की राजधानी बेंगलुरु में चलाए गए डिमोलिशन ड्राइव ने कांग्रेस के अंदर मतभेद उजागर कर दिए हैं। विरोध प्रदर्शन, विपक्षी दलों की आलोचना और पार्टी के अंदरखाने में उठ रही आवाजों के बीच कांग्रेस आलाकमान ने कर्नाटक सरकार को संयम और संवेदनशीलता बरतने की नसीहत दी है। यह पूरा मामला बेंगलुरु के बाहरी इलाके में येलहंका के पास कोगिलू गांव का है। यहां तोड़फोड़ की कार्रवाई ने कांग्रेस पार्टी के अंदर खलबली मचा दी है। इस कार्रवाई के बाद विरोध प्रदर्शन तेज हो गए और विपक्ष के हमलों के साथ-साथ कांग्रेस के अंदर से भी असहज सवाल उठने लगे हैं, जिससे कर्नाटक सरकार बचाव के मोड में आ गई है।

मीडिया रिपोर्ट के मुताबिक कांग्रेस महासचिव केसी वेणुगोपाल ने शनिवार को कर्नाटक के सीएम सिद्धारमैया और डिप्टी सीएम डीके शिवकुमार से इस मुद्दे पर बात की। वेणुगोपाल ने कोगिलू गांव से लोगों को हटाने की कार्रवाई को लेकर गहरी चिंता जताई और कहा कि इस तरह के कदमों में कहीं ज्यादा सावधानी, संवेदनशीलता की जरूरत होती है। उन्होंने साफ कहा कि फैसलों में मानवीय कीमत को सबसे ऊपर रखा जाना चाहिए। वेणुगोपाल के मुताबिक अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी इस पूरी कार्रवाई के तरीके को लेकर सहज नहीं है। उन्होंने कहा कि सिद्धारमैया और डीके शिवकुमार दोनों ने भरोसा दिलाया है कि वे खुद प्रभावित परिवारों से संवाद करेंगे, शिकायत निवारण तंत्र बनाएंगे और पुनर्वास व राहत सुनिश्चित करेंगे।

इस बीच सोशल डेमोक्रेटिक पार्टी ऑफ इंडिया और स्थानीय लोगों ने विरोध प्रदर्शन किए। प्रदर्शनकारियों का आरोप है कि सरकार ने कमजोर और गरीब परिवारों को बिना पर्याप्त वैकल्पिक व्यवस्था के बेघर कर दिया है। उन्होंने तुरंत पुनर्वास, अस्थायी आश्रय और बुनियादी सुविधाएं उपलब्ध कराने की मांग की। एसडीपीआई के कर्नाटक महासचिव मुजाहिद पाशा ने सरकार पर तीखा हमला बोला। उन्होंने आरोप लगाया कि कांग्रेस वही बेदखली की राजनीति अपना रही है, जिसकी वह पहले आलोचना करती रही है। मंत्रियों के इस दावे को भी उन्होंने खारिज कर दिया कि यहां रहने वाले लोग अवैध प्रवासी थे या यह जमीन केवल ठोस कचरा प्रबंधन के लिए आरक्षित थी। पाशा ने केरल के सीएम पिनराई विजयन की आलोचना का हवाला दिया और कहा कि यह मामला अब सिर्फ कर्नाटक तक सीमित नहीं रहा, बल्कि राष्ट्रीय स्तर पर चर्चा का विषय बन चुका है।

सीएम सिद्धारमैया ने कार्रवाई का बचाव करते हुए कहा कि येलहंका के पास कोगिलू बदवाने क्षेत्र की जमीन कचरा डंपिंग साइट है, जो लोगों के रहने के लिए उपयुक्त नहीं है और उस पर अतिक्रमण किया गया था। उन्होंने कहा कि परिवारों को पहले ही कई बार नोटिस जारी कर वहां से हटने को कहा था, लेकिन कोई प्रतिक्रिया नहीं मिली, जिसके बाद बेदखली की कार्रवाई जरूरी हो गई। उन्होंने बेंगलुरु महानगर पालिका के आयुक्त को निर्देश दिए हैं कि प्रभावित लोगों के लिए अस्थायी आश्रय, भोजन और अन्य जरूरी सुविधाओं की व्यवस्था की जाए। उन्होंने यह भी कहा कि वहां रहने वाले अधिकतर लोग स्थानीय नहीं बल्कि प्रवासी मजदूर हैं, फिर भी मानवीय दृष्टिकोण से उनके लिए उचित आवास की व्यवस्था की जाएगी।

एसआईआर पर बंगाल के प्रशासनिक अधिकारियों को आपत्ति, चुनाव आयोग को लिखे पत्र से मचा हंगामा

नई दिल्ली/कोलकाता (एजेंसी)। चुनाव आयोग द्वारा कराए जा रहे विशेष गहन पुनरीक्षण (एसआईआर) को लेकर पश्चिम बंगाल प्रशासनिक सेवा के अधिकारियों ने गंभीर सवाल खड़े कर दिए हैं। पश्चिम बंगाल सिविल सर्विस ऑफिसर्स एसोसिएशन ने राज्य के मुख्य निर्वाचन अधिकारी (सीईओ) को पत्र लिखकर आशंका जताई है। मतदाता सूची में नाम जोड़ने और हटाने की प्रक्रिया में केंद्रीय चुनाव आयोग, निर्धारित वैधानिक व्यवस्था को दरकिनार कर रहा है।

एसोसिएशन ने अपने पत्र में स्पष्ट किया है। एसआईआर के तहत मतदाता सूची से नाम हटाने या नोटिस जारी करने का अधिकार निर्वाचक रजिस्ट्रीकरण अधिकारी (ईआरओ) के पास होता है। मौजूदा प्रक्रिया में ईआरओ की भूमिका सीमित कर दी गई है। अधिकारियों का कहना है , चुनाव आयोग के एक केंद्रीकृत सॉफ्टवेयर सिस्टम के जरिए सीधे नोटिस जनरेट हो रहे हैं। जिससे स्थानीय स्तर पर जांच और सुनवाई की गुंजाइश समाप्त हो गई है।

पत्र में उल्लेख किया गया है। कई ईआरओ के लॉग-इन पर पहले से तैयार नोटिस दिखाई दे रहे हैं। इससे ईआरओ को यह तय करने का अवसर नहीं मिल रहा। वह किन मामलों में नोटिस जारी करे या किन मामलों में सुनवाई आवश्यक है। इससे बड़े पैमाने पर केंद्रीय पोर्टल के माध्यम से बड़ी संख्या में वोटर डिलीशन हो सकता है। जिसमें स्थानीय अधिकारियों की भूमिका औपचारिक रह जाएगी। इससे बीएलओ और ईआरओ को मतदाताओं के कोपभाजन का शिकार होना पड़ सकता है। प्रशासनिक अधिकारियों ने चेतावनी दी है, यदि किसी मतदाता का नाम सूची से हटाया जाता है। तो आम जनता इसका दोष स्थानीय ईआरओ पर डालेगी, जबकि वास्तविक निर्णय प्रक्रिया में ईआरओ को पूरी तरह से बाहर कर दिया गया है। इससे अधिकारियों की निष्पक्षता पर सवाल उठेंगे। चुनावी प्रक्रिया की विश्वसनीयता प्रभावित होगी।

एसोसिएशन का कहना है, एसआईआर जैसी संवेदनशील प्रक्रिया में सॉफ्टवेयर आधारित निर्णय की स्थान पर स्थानीय स्तर पर दस्तावेजों की जांच, सुनवाई और मानवीय हस्तक्षेप जरूरी है। चुनाव आयोग से मांग की है, ईआरओ को उनकी वैधानिक शक्तियां पूरी तरह सौंपी जाएं। किसी भी प्रकार की डिलीशन प्रक्रिया से पहले पारदर्शी सुनवाई सुनिश्चित की जाए।

इस पत्र के सामने आने के बाद एसआईआर को लेकर राजनीतिक और प्रशासनिक हलकों में बवंडर मच गया है। विपक्षी दल इसे मतदाता सूची में संभावित हेरफेर से जोड़कर देख रहे हैं। चुनाव आयोग की ओर से अब तक इस मामले पर कोई प्रतिक्रिया सामने नहीं आई है।

प्रशासनिक अधिकारियों की इस आपत्ति ने एसआईआर की पारदर्शिता और निष्पक्षता को लेकर देश भर में एक नई बहस छिड़ गई है।

आंतकी संगठनों के टारगेट पर 'वाइट कॉलर मॉड्यूल'...संदेह कम और समाज में घुले-मिले रहते

भारतीय खुफिया एजेंसियों के लिए बढ़ी चिंता

नई दिल्ली (एजेंसी)। भारत में आतंकवाद के बदलते स्वरूप ने सुरक्षा एजेंसियों की चिंता बढ़ाई है। हालिया इनपुट्स मिले हैं कि अल-कायदा जैसे आतंकी संगठन अब पारंपरिक हिंसक हमलों के बजाय एक नए, डिजिटल और वैचारिक मॉडल पर काम कर रहे हैं। इस रणनीति का उद्देश्य तात्कालिक दहशत फैलाने से अधिक लंबे समय में विचारधारा के द्वारा प्रभाव बनाना है।

दरअसल दिल्ली में हुए आतंकी हमले के बाद ÷वाइट कॉलर मॉड्यूल÷ पर फोकस बढ़ा है। इसी कड़ी में पुणे एंटी-टेररिज्म स्क्वाड द्वारा अक्टूबर 2025 में सॉफ्टवेयर प्रोफेशनल जुबैर इलियास हंगरगेकर की गिरफ्तारी को एक अहम केस माना जा रहा है। जांच एजेंसियों के मुताबिक, जुबैर अल-कायदा और उसके दक्षिण एशियाई संगठन से वैचारिक रूप से जुड़ा हुआ था। उसके डिजिटल फुटप्रिंट—जैसे एन्क्रिप्टेड कम्युनिकेशन, संग्रहित प्रोपेगेंडा सामग्री और क्लोज्ड ऑनलाइन ग्रुप्स में सक्रियता ने साफ कर दिया हैं कि कट्टरपंथ अब ज्यादा ÷ऑनलाइन और छिपा हुआ÷ हो चुका है।

इस मामले में सबसे बड़ी चिंता की बात यह हैं कि आरोपी का कोई आपराधिक इतिहास नहीं था। वह पढ़ा-लिखा, पेशेवर और सामाजिक रूप से स्थापित व्यक्ति था। यही पैटर्न हाल के अन्य मामलों में भी दिखा है, जिसमें डॉक्टर और दूसरे सम्मानित पेशों से जुड़े लोग शामिल हैं। खुफिया एजेंसियों का मानना है कि अल-कायदा जानबूझकर इसतरह लोगों को टारगेट कर रहा है जिन पर संदेह कम होता है, जो समाज में आसानी से घुले-मिले रहते हैं और जिनकी बातों को विश्वसनीयता के साथ सुना जाता है। डिजिटल प्लेटफॉर्म इस नए मॉडल की रीढ़ हैं। स्मार्टफोन और इंटरनेट की बढ़ती पहुंच का फायदा उठाकर आतंकी संगठन अपनी विचारधारा फैलाते हैं। इस प्रक्रिया में खुली हिंसा नहीं होती, बल्कि धीरे-धीरे नैरेटिव गढ़ा जाता हैं, शिकायतें उभारी जाती हैं।

खुफिया रिपोर्ट्स के अनुसार, अल-कायदा भारत को फिलहाल तात्कालिक ऑपरेशनल थिएटर की बजाय एक लॉन्ग-टर्म वैचारिक मंच के रूप में देख रहा है। यहां उद्देश्य हमदर्द तैयार करना, सहानुभूति पैदा करना और इसतरह के लोग विकसित करना है जो बाहरी तौर पर ÷नॉर्मल÷ दिखें, लेकिन अंदरूनी तौर पर कट्टर विचारधारा से जुड़े हों। यह रणनीति संगठन को जल्दी पकड़ में आने से बचाती है और समय के साथ गहरी पैठ बनाने में मदद करती है।